



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/चैत्र 7, 1939

No. 68]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

प्रारंभिक जाँच परिणाम

विषय : चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-(टीडीआई) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/36/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. यतः मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-(संक्षेप में टीडीआई) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 5.10.2016 की अधिसूचना सं. 14/36/2016-डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और

पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

क. प्रक्रिया

4. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. आवेदन की प्रारंभिक जाँच से कतिपय कमियों का पता चला जिन्हें बाद में आवेदक द्वारा सुधार दिया गया। अतः आवेदन को उचित ढंग से दस्तावेजी माना गया। प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध जाँच की शुरुआत करने का निर्णय लिया।
- ii. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्यवाही की शुरुआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- iii. संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अलावा, कोरिया गणराज्य की सरकार को भारत और कोरिया गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुच्छेद 2.14 के उपबंधों के अनुसार संबद्ध आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में उनके दूतावास के माध्यम से सूचित किया गया।
- iv. जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों से दूतावासों, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार उनसे जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। इन अनुरोधों को प्रस्तुत करने के लिए जहाँ आवश्यक हो प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा को बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- v. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भेजी थी। आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षों को भी भेजी गई थी। भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर उनके उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था।
- vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए उन्हें निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं : -
 - क) यनताइ जुली फाइन कैमिकल कं. लि.,
चीन जन. गण.
 - ख) चांगडू दहुआ ग्रुप कं. लि.,
चीन जन. गण.
 - ग) शंघाई बीएसएफ पालीयूरेथेन कं.लि.
चीन जन. गण.
 - घ) बायर मैटेरियल साइंस (चाइना) कं. लि.
चीन जन. गण.
 - ङ) मितसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स,
जापान
 - च) निप्पोन पालीयूरेथेन इंडस्ट्री कं. लि.
जापान
 - छ) हानवा फाइन कैमिकल कं. लि.
कोरिया गणराज्य
 - ज) ओसीआई कापॉरेशन/ओसीआई कं. लि.
कोरिया गणराज्य
 - झ) बीएसएफ कं. लि.
कोरिया गणराज्य
- vii. जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने उत्तर दिया है:
 - क) हानवा फाइन कैमिकल कापॉरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ख) टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूआई
 - ग) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि., कोरिया गणराज्य
 - घ) आईएमएस कापॉरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ङ) एवरलाइट कोरिया कं. लि., कोरिया गणराज्य

च) बीएसएफ कं. लि., कोरिया गणराज्य

viii. उक्त कंपनियों के अलावा चीन जन. गण. की निम्नलिखित कंपनियों ने जाँच में भाग लेने में रुचि दिखाई यद्यपि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं करने का दावा किया।

क) वेनहुआ कैमिकल ग्रुप कं. लि.

ख) चेंगडू दहुआ होल्डिंग कं. लि.

ix. निम्नलिखित निर्यातकों ने भी जांच शुरूआत के बाद कतिपय अनुरोध प्रस्तुत किए हैं :

क) केवेस्ट्रो (हांग कांग) लिमिटेड

ख) मितसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स आईएनसी

x. आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

1. शीला ग्रुप कं.
2. तिरूपति फोम
3. कर्लोन लि.
4. स्प्रिंगवैल मैटरेस
5. सनराइज फोम प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
6. एम एच पालीमर्स
7. प्यारेलाल फोम (साउथ)
8. जिंदल फोम
9. अलाइड फोम
10. ड्यूरा पफ
11. फैन्सी फोम
12. हिंदुस्तान पालीफोम
13. श्री मालानी फोम्स
14. प्राइम कम्फर्ट्स
15. स्प्रिंगफील पालीयूरेथेन्स
16. आदि पालीमर्स

xi. प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर देते हुए जवाब दिया है :

क) शीला फोम लि.

xii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा उसकी बिक्री करने की ईष्टतम लागत ज्ञात की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा अथवा नहीं।

xiv. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xv. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया गया था। आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना जहां लागू हो, पर वर्तमान प्रारंभिक जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

xvi. प्राधिकारी ने पीओआई के रूप में 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, (12 महीने) की अवधि पर विचार किया है ताकि बिल्कुल हाल के आकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। यह जांच 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (पीओआई) की अवधि में की गई थी। तथापि क्षति विश्लेषण में प्रवृत्तियों की जाँच में अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 - मार्च 14, अप्रैल 14 - मार्च 15 और जांच की अवधि को शामिल किया गया।

xvii. आवेदक द्वारा आवेदन में द्वितीयक स्रोत (आईबीआईएस) के अनुसार आयात संबंधी सूचना प्रदान की गई है और जाँच शुरूआत के स्तर

पर उसे स्वीकार किया गया है। तथापि, अनंतिम जाँच परिणामों के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्षों और पीओआई के लिए देश में संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य के प्रयोजनार्थ डीजीसीआईएंड से यथा एकत्रित सौदावार आयात आकड़ों पर भरोसा किया है।

xviii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है या जाँच में काफी बाधा डाली है, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच परिणामों को रिकार्ड किया है।

xix. इस अनंतिम जाँच परिणाम में *** चिह्न किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xx. सीमाशुल्क आकड़ों के अनुसार पीओआई के लिए अमरीकी डालर से भारतीय रुपये में परिवर्तन की विनिमय दर को 65.91 भारतीय रुपये प्रति अमरीकी डालर माना गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण., जापान और कोरिया के मूल का अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-टीडीआई है।

6. टोलीन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$ है। यह संभव आइसोमर्स में से दो वाणिज्यिक रूप में महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (91-08-7)। 2, 4-टीडीआई को शुद्ध रूप में उत्पादित किया जाता है, परंतु टीडीआई को प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रणों में बेचा जाता है। वर्तमान जाँच में पीयूसी उस टीडीआई से संबंधित है जिसकी आइसोमर मात्रा का अनुपात (80:20) है और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

7. टीडीआई एक स्वच्छ तरल होता है और उसका प्रयोग फ्लेक्सिबल पालीयूरेथेन फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गैस्केट, खेल और चिकित्सा प्रयोग के लिए सुरक्षा पैडों, आटोमोबाइल:सीटों, फर्नीचर, लाइनिंग, सन वाइजर आदि, मैकिंग: इलेक्ट्रानिक मदों, शीतित खाद्यों, दवाइयों, आडियो-वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि में होता है।

8. चूंकि टीडीआई एक कार्बनिक रसायन है इसलिए इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत और आगे उपशीर्ष 29291020 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, जो टोलीन डि-आइसोसायनेट से संबंधित है। तथापि जैसा आवेदक ने बताया है इस शीर्ष में आइसोमर (80:20) से इतर कतिपय ग्रेड भी शामिल हैं और इसलिए वर्गीकरण के बल सांकेतिक है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात कुछ अन्य उपशीर्षों जैसे 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 और 39095000 के अधीन भी किए जाने की सूचना मिली है। डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आकड़ों की जाँच से पता चलता है कि पीओआई के दौरान आयात प्राथमिक रूप से उपशीर्ष सं. 29291020 के अधीन हुए हैं और उपशीर्ष 29291010 और 29291090 के अधीन भी काफी आयात हुए हैं। इस प्रकार, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जाँच के दायरे पर और अनुशंसित किए जाने वाले किसी उपाय, यदि कोई हो, पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

9. एक निर्यातक अर्थात् मिसुई कैमिकल्स एंड एसकेसी पालीयूरेथेन्स इंक (एमसीएनएस) को छोड़कर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों में से किसी ने भी पीयूसी की परिभाषा और दायरे के संदर्भ में कोई अनुरोध नहीं किया है। एमसीएनएस ने प्राधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या दो उत्पादों अर्थात् "टीएम" और "एमटी" को पीयूसी के दायरे में शामिल/उससे बाहर किया गया है अथवा नहीं। एमसीएनएस ने यह अनुरोध किया है कि टीएम 50 प्रतिशत या अधिक टीडीआई और पालीमेरिक एमडीआई (पालीमिथलेनेपालीफिनाइल/पालीआइसोसाइनेट या पीएमडीआई) का मिश्रण है। इसके अलावा, एमटी 50 प्रतिशत से कम टीडीआई और आशोधित मोनोमेरिक एमडीआई, 4.4' - (डिफिनाइल मिथेनआइसोसाइनाइट) का मिश्रण है। एमसीएनएस ने यह भी बताया है कि टीडीआई और टीएम/एमटी के रासायनिक संघटन में काफी अंतर होता है और वास्तव में टीडीआई को प्रयोग टीएम और एमटी की उत्पादन/विनिर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। एमसीएनएस के अनुरोधों की जाँच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी की परिभाषा और दायरे को जाँच शुरूआत अधिसूचना और पीयूसी से संबंधित अनंतिम जाँच परिणाम में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस प्रकार, यहां उक्त परिभाषा को पूरा करना ही वर्तमान जाँच के दायरे के अधीन आता है और न कि किसी अन्य उत्पाद के लिए।

समान वस्तु

10. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में सामान्य मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

11. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अधीन इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

12. प्राधिकारी ने दावों की जाँच की है और नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी विरोधी पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

13. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

14. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं। इस प्रकार, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है; वास्तव में घरेलू उत्पादन में उनका 100 प्रतिशत हिस्सा है।

15. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समय घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

16. यह नोट किया जाता है कि आवेदन जिसके आधार पर वर्तमान पाटनरोधी जाँच शुरू की गई है भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग के रूप में मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के दावों के अनुसार मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में कोई विरोधी अनुरोध नहीं किया है।

17. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक हैं और वर्तमान जाँच के प्रयाजनार्थ नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र है।

18. चूंकि आवेदक के उत्पादन का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा वस्तुतः 10 प्रतिशत हिस्सा बनता है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

घ. गोपनीयता

19. गोपनीयता के पहलू के संबंध में उत्पादक/निर्यातक/आयात/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

20. गोपनीयता और सूचना के प्रकटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए कतिपय अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों और आयातों द्वारा काफी अधिक गोपनीयता अपनायी गई है। ईक्यू उत्तरों और आईक्यू उत्तरों के एनसीवी अंश से पाटन और ऐसे प्रतिवादी पक्षों द्वारा देश में किए गए आयातों के संदर्भ में ऐसे पक्षों के दावों की तर्कसंगत समझ नहीं बनती है।
- दस्तावेजों के एनसीवी अंश को इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग उनका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता है।
- क्रमशः उत्पादक/निर्यातक/आयातक द्वारा दी गई इस मूल सूचना की गोपनीयता का दावा नहीं किया जा सकता है :

क. संबद्ध देशों से निर्यातों/आयातों की कुल मात्रा संबंधी सूचना

ख. संबद्ध देशों से आयातों की औसत कीमत

ग. धारक कंपनी का ब्यौरा और निर्यातक/व्यापारी द्वारा उत्तर दिए जाने पर संबंधित उत्पादकों का नाम वास्तव में, किसी भी भागीदार निर्यातक/व्यापारी ने ऐसे संबंधित उत्पादकों के नाम नहीं बताये हैं जिनके उत्पाद को ऐसे पक्षों ने निर्यात किया है।

- iv. यद्यपि नियमावली में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्ष के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है, तथापि प्रतिवादी पक्षों ने उनके लिए सुविधाजनक ढंग से उपयोग किया है और वस्तुतः उनके द्वारा पाटित आयातों के संबंध में याचिकाकर्ता को वास्तविक स्थिति जानने से अवरूद्ध किया है। प्रतिवादी पक्षों द्वारा अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता यूरोपीय संघ – चीन से कतिपय आयरन या स्टील फास्तेनर संबंधी पाटनरोधी उपायों (डब्ल्यूटी/डीएस 397/एबी/आर दिनांक 15 जुलाई, 2011) में अपीलीय निकाय के निष्कर्षों का उल्लंघन है जिसमें अपीलीय निकाय ने गोपनीयता से संबंधित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 और 6.5.1 की व्याख्या की है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

21. यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रतिवादी पक्ष ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कतिपय सूचना संबंधी गोपनीयता पर प्रश्न नहीं उठाया है। तथापि प्रतिवादी पक्षों के गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कतिपय अनुरोध किए गए हैं। गोपनीयता/प्रकटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच और विचार किया गया है :

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियम (7), (2), नियम 12 के उपनियम (2) (3), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

23. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रदान करने का निदेश दिया गया। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों का एक सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध रखा। इस अनंतिम जाँच परिणाम में विभिन्न चर्चाएं गोपनीयता के पहलू के संबंध में घरेलू उद्योग की अन्य दलीलों के संबंध में स्वतः-स्पष्ट हैं।

ड. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

क) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार

24. वर्तमान जाँच दिनांक 5.10.2016 को शुरू की गई और वर्तमान जाँच में चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयाजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने का विकल्प खुला था। पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन (वर्तमान मामले में) का (के) निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या :-

क. कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में

बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

- ख. इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- ग. इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- घ. विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

25. यह नोट किया जाता है कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक, जिसने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, ने ईक्यू उत्तर और एमईटी उत्तर प्रस्तुत करके वर्तमान जॉच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, चीन जन. गण. के विरुद्ध एनएमई की धारणा का चीन के उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जॉच में खंडन नहीं किया है।

एमईटी के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

26. यह नोट किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातों/अन्य हितबद्ध पक्षों कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किए गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. चीन जन. गण. को वर्तमान जॉच के लिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य पैरा 7 अनुबंध के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. चीन के उत्पादकों को भारतीय प्राधिकारी और ईक्यू, यूएसए, आस्ट्रेलिया आदि जैसे अन्य देशों द्वारा हाल में समाप्त जांचों सहित अनेक जांचों में एमईटी दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि चीन जन. गण. को विभिन्न पाटनरोधी जॉच में गैर बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) माना गया है।
- ग. एमईसी दर्जा प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा एमईटी की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही दिया जाना चाहिए अन्यथा नहीं। इस प्रकार पाटनरोधी नियम के अनुबंध 1 के पैरा 8(3) की अपेक्षाओं को एमईटी दर्जा प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से पूरा करना होगा।
- घ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस इस्थिति में नहीं दिया जा सकता है जबकि एक प्रमुख शेयरधारक राज्य स्वामित्व/नियंत्रित कंपनी है।
- ङ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें बाजार मूल्य दर्शाती हों। यह शब्द कि 'बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाना' की व्यापक रूप से इस अर्थ में व्याख्या की गई है कि इन निविष्टियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए। यह तथ्य कि ऐसी कीमतें चीन में प्रचलित कीमतों से तुलनीय है बिल्कुल सही नहीं है।
- च. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है। बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को ऐसी स्थिति में अस्वीकार किया जाए जबकि चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) से संगत हैं।
- छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी चीन के निर्यातक नियामों के अधीन प्रत्येक निर्धारित मापदंड को पूरा करने के परीक्षण को पास न कर लें।
- ज. यह दायित्व चीन के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों का है कि वे सिद्ध करें कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में काम कर रहे हैं और पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
- झ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें। यदि समूह बनाने वाली एक यह अधिक कंपनी ने उत्तर नहीं दिया तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जे को इस तथ्य कि समूह की अन्य कंपनियों जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल हैं, ने उत्तर प्रस्तुत किया है, पर विचार किए बिना, अस्वीकार किया जाना चाहिए।

- ज. ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं अपितु उसे किसी अन्य पक्ष से अधिग्रहीत किया है बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तक तब नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध हो।
- ट. वर्तमान जॉच में ऐसा कोई सहयोगी उत्पादक/निर्यातक नहीं है जिसने एमईटी प्रश्नावली के अनुसार समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करके एनएमई दर्जे की धारणा का खंडन किया हो चीन जन गण को केवल इसी तथ्य के आधार पर गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए।
- ठ. आवेदक ने पाटनरोधी नियम और नियम के संगत अनुबंध में विनिर्दिष्ट विधि से उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को प्रस्तुत किया है। ऐसी गणनाओं का ब्यौरा एनसीवी आवेदन में दिया गया है जो विस्तृत है और सभी अनिवार्य विनिर्देशनों वाला है। यदि संबंधित उत्पादक/निर्यातक सार्थक रूप से सहयोग न करें तो प्राधिकारी इस जॉच के प्रयोजनार्थ सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना पर भरोसा कर सकते हैं।
- ड. चीन एक्सेसन संधि के उपबंधों के वर्तमान मामले में कोई निहितार्थ नहीं है क्योंकि वर्तमान मामला 5.10.2016 को शुरू हुआ है और चुनी गई पीओआई अप्रैल 2015 – मार्च 2016 तक है।
- ढ. एचएफसीसी द्वारा दायर किए गए इक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह कंपनी अर्थात् हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) 29 फरवरी, 2016 को हानवा कैमिकल कार्पोरेशन (एचसीसी) के व्यवसाय प्रभाग में विलयित हुई है। तथापि इक्यू उत्तर एचएफसीसी को किसी विधिक या वास्तविक औचित्य के बिना कंपनी के रूप में ब्योरे प्रदान करके दायर किया गया है।
- ण. पूरे इक्यू उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर एचसीसी को तथ्य देने वाली कंपनी और न कि एचएफसीसी को मानते हुए दिया जाना चाहिए था जिसका अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया। इस परिदृश्य में, प्राधिकारी को एचएफसीसी के पूरे उत्तर को गलत और अधूरा मानना चाहिए और इसकी कोई विधिक साध्यता नहीं है।
- त. सभी प्रश्नों का उत्तर एचएफसीसी को संगत कंपनी मानते हुए दिया गया है। उदाहरण के लिए एचएफसीसी के शेयरधारकों की सूची, शामिल कारखानों की सूची आदि दी गई है जबकि तथ्यों के अनुसार संगत यह है कि प्रकट तथ्य एचसीसी न कि एचएफसीसी जिसका अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया, द्वारा कंपनी के रूप में प्रश्नों के उत्तर हैं, जो पीओआई के बिल्कुल भीतर हैं। प्रदत्त गलत और अनुचित उत्तरों को इस समय नहीं सुधारा जा सकता है और उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- थ. यह नोट किया जा सकता है कि एचसीसी का कोई भी उत्तर एचएफसीसी के किसी उत्तर से बिल्कुल अलग होगा और एचसीसी के बजाय एचएफसीसी द्वारा दायर इक्यू उत्तर से प्राधिकारी को पाटन की किसी जॉच में मदद नहीं मिलेगी। एचएफसीसी का अस्तित्व 29 फरवरी 2016 को समाप्त हो गया और ऐसी स्थिति में इक्यू का उत्तर देने वाली संगत कंपनी एचसीसी है और एचसीसी ने इस आशय का कोई इक्यू उत्तर नहीं प्रस्तुत किया है।
- द. इक्यू उत्तर में पूरे प्रश्नों का उत्तर एचसीसी को देना चाहिए था और एचएफसीसी के बजाय एचसीसी को ही अलग मार्जिन की मांग करनी चाहिए। इस प्रकार, यदि एचएफसीसी को अलग मार्जिन दिया जाता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि एचएफसीसी अस्तित्व में नहीं है।
- ध. एनसीवी उत्तर में एचसीसी ने अनुरोध किया है कि भारत को पीयूसी के निर्यात में एक श्रृंखला शामिल है तथापि उस निर्यातक का नाम नहीं बताया गया है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस शामिल निर्यातक ने निर्यातक उत्तर प्रस्तुत किया है।
- न. एचसीसी ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है और श्रृंखला के निर्यातक का नाम नहीं बताया है। निर्यातक का नाम कैसे गोपनीय हो सकता है? क्या यदि अलग मार्जिन दिया भी जाता है तो प्राधिकारी किसी निर्यातक के नाम को गोपनीय मान सकते हैं? इस प्रकार मूल सूचना को गोपनीय रखना गोपनीयता के उपबंधों का घोर उल्लंघन है और गोपनीयता का ऐसा दावा बिल्कुल गलत है जिसे प्राधिकारी को अस्वीकार करना चाहिए।
- प. टीजे एएल मुलूक द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि टीजे एएल मुलूक संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि इक्यू उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को टीजे एएल मुलूक द्वारा निर्यात किया गया?
- फ. संगत उत्पादक द्वारा पूरे इक्यू उत्तर के रूप में सहयोग के बिना टीजे एएल मुलूक के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

- ब. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि इक्यू उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा निर्यात किया गया?
- भ. संगत उत्पादक द्वारा पूरे इक्यू उत्तर के रूप में सहयोग के बिना पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- म. आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि आईएमएस कार्पोरेशन संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि इक्यू उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा निर्यात किया गया?
- य. संगत उत्पादक द्वारा पूरे इक्यू उत्तर के रूप में सहयोग के बिना आईएमएस कार्पोरेशन के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- र. एवरलाइट कोरिया कं. लि. द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर से यह स्पष्ट है कि एवरलाइट कोरिया कं. लि. संबद्ध वस्तु का केवल निर्यातक/व्यापारी है और न कि उत्पादक। तथापि इक्यू उत्तर में यह प्रकटन नहीं है कि संबद्ध वस्तु के किसके उत्पादन को एवरलाइट कोरिया कं. लि. द्वारा निर्यात किया गया?
- ल. संगत उत्पादक द्वारा पूरे इक्यू उत्तर के रूप में सहयोग के बिना एवरलाइट कोरिया कं. लि. के उत्तर पर अलग मार्जिन निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जॉच

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 'बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार' के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के अधीन निर्धारित संगत उपबंध निम्नानुसार हैं :

8 (1) "गैरबाजार- अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी- को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था- वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है;

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं;

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

[(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो]

28. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन के शामिल होने के नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है :

'गैट 1994 का अनुच्छेद 4, टैरिफों और व्यापार हेतु सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद 4 के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) और एससीएम करार चीन के डब्लूटीओ के सदस्य के रूप में आयात शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित से संगत होने पर लागू होंगे :

(क) गैट 1994 का अनुच्छेद 4 और पाटनरोधी करार के अधीन कीमत तुलनीयता निर्धारित करने के लिए आयातक डब्लूटीओ देश या तो चीन की कीमतों या जाँच के अधीन उद्योग की लागतों या ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियम के अधीन घरेलू कीमतों और चीन में लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित हों :

(i) यदि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण के लिए जाँच के अधीन उद्योग हेतु चीन की कीमतों या लागतों का प्रयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्लूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो परंतु यदि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकता हो कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अधीन कार्यवाही में, जब एससीएम करार के संगत उपबंधों के अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14 (घ) में वर्णित सस्मिडी पर विचार करना लागू हो : तथापि यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाई हो, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य सस्मिडी लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जिसमें इस संभावना पर विचार हो कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें हमेशा समुचित बेंचमार्कों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों के प्रयोग में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्लूटीओ सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्लूटीओ सदस्य पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सस्मिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अधीन चीन के बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश सिद्ध होने पर, उप पैराग्राफ (क) के उपबंध समाप्त हो जाएंगे परंतु यह कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में शामिल होने की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था के मापदंड शामिल हों। किसी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के उपबंध शामिल होने की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा चीन को आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार यह सिद्ध करना होगा कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं उस उद्योग या क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के उपबंध उस उद्योग या क्षेत्र पर अब लागू नहीं होते हैं।'

29. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराग्राफ के उपबंध चीन के शामिल होने की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि पाटन के घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का तथ्य जाँच अवधि के आधार पर सिद्ध हो गया है इसलिए जाँच अवधि के दौरान प्रचलित स्थिति ही संगत, समुचित है और वर्तमान जाँच के लिए आवश्यक है। वर्तमान समीक्षा के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से मार्च 2016 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ जाँच की अवधि के दौरान मौजूद था इसलिए यदि जाँच के अधीन उत्पादक उस उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद के उत्पादक उद्योग में स्पष्ट रूप से बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं न दिखा सकते हों कि प्राधिकारी ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत और अन्य डब्लूटीओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जॉचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातक द्वारा इस धारणा के खंडन के अधीन माना गया है। तथापि पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कोई भागीदारी नहीं की गई है इसलिए यह नोट किया जाता है कि एनएमई की धारणा जो पीओआई के दौरान प्रचलित थी का नियम के अधीन खंडन नहीं किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि जॉच 5.10.2016 को शुरू हुई थी और वर्तमान जॉच के लिए निर्धारित पीओआई अप्रैल 2015-मार्च 2016 है, इसलिए चीन एक्सेसन संधि के उपबंध जो कहते हैं कि डब्लूटीओ सदस्य चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध किसी पाटनरोधी जांच के मामले में 11 दिसंबर, 2016 तक एनएमई पाटनरोधी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान जॉच में भी चीन जन. गण. के संदर्भ में लागू होते हैं।

31. इसे देखते हुए, प्राधिकारी ने जॉच की कार्रवाई की है।

32. इक्यू उत्तरों की सत्यता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाये गए मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनंतिम जॉच परिणाम में उचित स्थानों पर मुद्दों का समाधान किया गया है, जो स्वतः स्पष्ट है।

ख) सामान्य मूल्य का निर्धारण

33. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों से संबंधित उपबंध

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उपबंध है कि:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

35. इन नियमों के अनुसार, एनएमई देशों (वर्तमान मामले में चीन) में सामान्य मूल्य को निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है :

क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर, या

ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में परिकलित मूल्य, या

ग) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों की कीमत

घ) यदि उक्त विकल्पों से सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता हो तो, निर्दिष्ट प्राधिकारी समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत को तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करके विधिवत रूप से समायोजन द्वारा सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

i. चीन जन. गण.

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक जिन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, ने विहित ढग और तरीके से उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार, चीन जन. गण. से वर्तमान जाँच में कोई उत्पादक/निर्यातक नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-6 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की दशा में प्रचालनरत नहीं पाये गये हैं। इस परिस्थिति में, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं और प्राधिकारी को संबंधित नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश में लागत और कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री या तीसरे देश की निर्यात बिक्री तथा तीसरे देश में ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत और सहयोग संबंधी पूरे और विस्तृत आकड़े अपेक्षित होंगे। इस बाजारों में प्रचलित कीमत और लागत के संबंध में ऐसी कोई सूचना आवेदक अथवा प्रतिवादी निर्यातक ने प्रदान नहीं की है न ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना प्राप्त हुई है, न ही चीन की कंपनियों ने इस स्तर पर बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश के संबंध में कोई दावा किया है। अतः प्रारंभिक निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करने की कार्यवाही की है।

38. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य अंतिम रूप से निर्धारित करते हैं। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य उत्पादन की परिकलित लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** डा./किग्रा. बनता है।

ii. जापान

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी के लिए कारखाना-द्वारा स्तर पर अंतिम भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो *** डा./किग्रा. बनता है।

iii. कोरिया गणराज्य

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से दो उत्पादकों अर्थात् मै. बीएएसएफ कंपनी लि. और मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा इक्यू उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं।

बीएएसएफ कंपनी लि.

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ कंपनी लि. (बीएएसएफ) ने संबद्ध वस्तु के उत्पादक और निर्यातक होने का दावा करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि उसने भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ ने परिशिष्ट-1 में घरेलू बिक्री के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

42. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण परीक्षण किया है। यदि लाभ कमाने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है और यदि लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद सौदों पर ही विचार किया गया है। यह भी नोट किया गया कि घाटे वाले सौदे कुल घरेलू बिक्री के 20 प्रतिशत से अधिक थे। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के परंतुक के अनुसार केवल लाभप्रद बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया की है।

43. बीएएसएफ ने छूट, अंतरदेशीय भाड़े और पैकिंग लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने अंतिम जाँच परिणामों के लिए सभी समायोजनों को स्वीकार किया है। तदनुसार, बीएएसएफ द्वारा उत्पादित पीयूसी के लिए कारखाना-द्वारा स्तर पर अंतिम भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो *** डा./किग्रा. बनता है।

हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन (एचएफसीसी) ने कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु का उत्पादक के रूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और बताया है कि उसने भारत को असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप

से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। एचएफसीसी ने यह भी बताया है कि कंपनी ने तीन निर्यातकों/व्यापारियों के जरिए भारत को पीयूसी का निर्यात किया है। और उन्होंने एचएफसीसी के साथ इक्यू का उत्तर प्रस्तुत किया है।

45. एचएफसीसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर की एचएफसीसी के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जाँच की गई है। यह नोट किया जाता है कि एचएफसीसी मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् टीडीए और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में सीडीसी का उत्पादन करती है। तथापि, एचएफसीसी ने उनके द्वारा आबद्ध रूप से उत्पादित इन मध्यवर्तियों की लागत शीट नहीं दी है। एचएफसीसी ने परिशिष्ट 5 में टीडीए और सीडीसी का ब्यौरा दिया है जिनके उनके द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती होने का दावा किया गया है, तथापि इन मध्यवर्ती के उत्पादन की कच्ची सामग्री का ब्यौरा नहीं दिया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि परिशिष्ट-4 में, संबद्ध वस्तु के *** मी.टन को अंतरण अंदर और बाहर दर्शाया गया है। एचएफसीसी द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर में विभिन्न परिशिष्टों में कमी और अंतरों को देखते हुए, प्राधिकारी इस स्तर पर ओसीटी परीक्षण के प्रयोजनार्थ एचएफसीसी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की उचित लागत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं और तदनुसार, एचएफसीसी के सामान्य मूल्य के दावों जिनमें विस्तृत सत्यापन अपेक्षित है, पर प्रारंभिक जाँच परिणामों के लिए विचार नहीं किया गया है। उक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर अनंतिम भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो *** डा./किग्रा. बनता है।

कोरिया गणराज्य में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर अनंतिम भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है जो *** डा./किग्रा. बनता है।

ग) निर्यात कीमत का निर्धारण

i. चीन जन. गण.

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंधित पीयूसी के लिए चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

ii. जापान

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंधित पीयूसी के लिए जापान में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

iii. कोरिया गणराज्य

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से दो उत्पादकों अर्थात् मै. बीएसएफ कंपनी लि. और मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा इक्यू उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि बीएसएफ कंपनी लि. द्वारा यह बताया गया है कि उन्होंने भारत को सीधे पीयूसी का निर्यात किया है तथापि हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन ने यह बताया है उन्होंने संबद्ध वस्तु का निर्यात असंबंधित निर्यातकों/व्यापारियों अर्थात् मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि., मै. आइएमएस कार्पोरेशन और मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. के जरिए किया है जिन्होंने इक्यू उत्तर प्रस्तुत किए हैं और प्राधिकारी से सहयोग कर रहे हैं।

50. निर्यातकों अर्थात् मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि., मै. आइएमएस कार्पोरेशन और मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. ने इक्यू उत्तर प्रस्तुत किए हैं और दावा किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

51. एक यूई मूल की व्यापारिक कंपनी मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने इक्यू उत्तर प्रस्तुत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का कोरियाई निर्यातक मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के जरिए निर्यात किया है।

क) बीएसएफ कंपनी लि.

52. प्राधिकारी बीएसएफ कंपनी लि. द्वारा प्रस्तुत इक्यू उत्तर से नोट करते हैं कि बीएसएफ कंपनी लि. ने पीओआई के दौरान सीधे भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। बीएसएफ ने अपने परिशिष्ट 2 में *** मी.टन के कुल निर्यात की जानकारी दी है और

अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीयूसी के संबंध में वीएएसएफ के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./ मी.टन बनती है।

ख) मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. (निर्यातक)

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा इक्यू उत्तर प्रस्तुत करके उनके मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. द्वारा दायर परिशिष्ट - 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के *** मी.टन का निर्यात किया है। पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीयूसी के संबंध में पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

ग) मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मै. आईएमएस कार्पोरेशन (निर्यातक)

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा इक्यू उत्तर प्रस्तुत करके उनके मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। आईएमएस कार्पोरेशन द्वारा दायर परिशिष्ट - 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के *** मी.टन का निर्यात किया है। आईएमएस कार्पोरेशन ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीयूसी के संबंध में आईएमएस कार्पोरेशन के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

घ) मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक) और मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. (निर्यातक)

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. द्वारा इक्यू उत्तर प्रस्तुत करके उनके मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के निर्यातक होने का दावा किया है। मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. द्वारा दायर परिशिष्ट - 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के *** मी.टन का निर्यात किया है। मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। तदनुसार, पीयूसी के संबंध में मै. एवरलाइट कोरिया कं. लि. के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

ड.) मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन(उत्पादक), मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. (निर्यातक) और मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूआई (व्यापारी)

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने इक्यू उत्तर प्रस्तुत किया है। मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने दावा किया है कि वे यूआई मूल की एक ट्रेडिंग कंपनी हैं और उन्होंने मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का भारत को पीओआई के दौरान कोरिया गणराज्य के निर्यातक अर्थात् मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के जरिए से संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा दायर परिशिष्ट - 2 में दर्शाया गया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के *** मी.टन का निर्यात किया है। मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने अंतरदेशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, बीमा और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और उनकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। तदनुसार, मै. हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित और मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. के जरिए निर्यातित पीयूसी के संबंध में मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो *** डा./किग्रा. बनती है।

च) कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जॉच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूसी के लिए अनंतिम भारित औसत निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है जो ***डा./किग्रा. बनती है।

घ) पाटन मार्जिन का निर्धारण

58. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नानुसार है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य - अम.डा./किग्रा.	निर्यात कीमत- अम.डा./किग्रा.	पाटन मार्जिन - अम.डा./किग्रा.	पाटन मार्जिन - %	पाटन मार्जिन रेंज- %
1	चीन जन. गण.	कोई	कोई	***	***	***	***	15-25
2	जापान	कोई	कोई	***	***	***	***	5-15
3	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि.	***	***	***	***	10- 20
4	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	एवरलाइट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	5-15
5	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	आईएमएस कार्पोरेशन	***	***	***	***	5-15
6	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	मै. पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. और मै. टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई	***	***	***	***	5-20
7	कोरिया गणराज्य	बीएसएसएफ कं. लि.	बीएसएसएफ कं. लि.	***	***	***	***	20-30
8	कोरिया गणराज्य	उक्त क्र. सं. 3 से 7 से इतर कोई अन्य उत्पादक	उक्त क्र. सं. 3 से 7 से इतर कोई अन्य निर्यातक	***	***	***	***	30-40

च. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच**i. क्षति जाँच**

59. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए क्षति संबंधी अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत निर्धारण जीएनएफसी, जो प्रमुख स्थानीय कंपनी है, जैसे समान उत्पाद के अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ तुलनीय है।
- शुल्क लगाने से एकाधिकार हो जाएगा क्योंकि जीएनएफसी एकमात्र उत्पादक है और वह भारतीय क्रेताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता को सीमित कर देगा।

- iii. शुल्क लगाने से भारत में मांग-पूर्ति का अंतर हो सकता है। भारतीय उद्योग 100 मांग की आपूर्ति नहीं कर सकता है। निम्नवर्ती उत्पादों के स्थानीय विनिर्माता पाटनरोधी शुल्क लागू होने से नुकसान में रहेंगे। इससे पीयूसी का प्रयोग करने वाले उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

60. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति से संबंधित अनुरोध संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

- i. याचिका में प्रदत्त क्षति संबंधी सूचना दर्शाती है कि यद्यपि मात्रा संबंधी मापदंड जैसे क्षमता, उत्पादन और बिक्री में सामान्य दृष्टि में सकारात्मक प्रवृत्ति रही है तथापि अनेक अन्य संकेतक जैसे क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, मालसूची का स्तर आदि क्षति की स्थिति दर्शाते हैं।
- ii. भारतीय बाजार में घरेलू मांग में 50 प्रतिशत बाजार हिस्सा कब्जा करके पाटित आयातों में प्रभुत्व बना रखा है जो काफी अधिक है और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की स्थिति काफी संवेदनशील हो गई है।
- iii. घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रमुख मापदंड जैसे लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय आदि पहले की सकारात्मक स्थिति से पीओआई के दौरान काफी नकारात्मक हो गये हैं और वास्तव में नियोजित पूंजी पर आय, वृद्धि आदि जैसे कारकों में गंभीर रूप से विकट वास्तविक क्षति की स्थिति दर्शाई है।
- iv. वास्तव में, घरेलू उद्योग को दो आधार वर्षों को छोड़कर क्षति अवधि में संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातक द्वारा आक्रामक पाटन के कारण भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।
- v. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को उसकी उत्पादन लागत से कम पर बेचना पड़ रहा है क्योंकि पाटित आयात उत्पादन लागत से कम कीमत पर उपलब्ध हैं जिससे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के लिए लाभकारी कीमत प्राप्त करने का उसका अधिकार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
- vi. पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और पीओआई के दौरान सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव भी स्पष्ट हैं। कीमत कटौती इस मामले में क्षति दर्शाने वाला कारक नहीं है क्योंकि कीमतें पहले से ही कम हैं और घरेलू उद्योग लागत से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है। इसलिए पंधुच कीमत से तुलना का प्रश्न नहीं उठता और वह अतार्किक है।
- vii. घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर काफी बढ़ गया है जो क्षति के स्पष्ट लक्षण दर्शाता है। उत्पादन में वृद्धि को मालसूची में वृद्धि के आलोक में देखा जाना चाहिए जो इस तथ्य को सिद्ध करती है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों द्वारा बाजार में अधिक बिक्री से रोका गया है।
- viii. विभिन्न आर्थिक मापदंडों का एक वस्तुनिष्ठ और समग्र मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के आधार पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव काफी अधिक है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग की स्थिति क्षति अवधि के आरंभिक दो वर्षों के बाद घाटा उठाने वाली कंपनी में बदल गई है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ix. यहां तक कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में मात्रा संबंधी मापदंड भी काफी दबाव में हैं क्योंकि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और वह समतुल्य स्तर से कम रहा है जबकि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है और पाटित आयातों के पास 50 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है।
- x. वास्तव में उत्पादन और बिक्री में मामूल वृद्धि को पाटित आयातों से कीमत संबंधी गंभीर प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग के सामने समग्र घाटे के कारण ऋणात्मक हो गई है। घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर बिक्री करनी पड़ी है जो लाभकारी नहीं है और वास्तव में उसकी उत्पादन लागत से कम है। घरेलू उद्योग ने इस प्रकार वास्तविक क्षति उठाई है और यह क्षति संबद्ध देशों से पाटन के कारण हुई है।
- xi. कोवेस्ट्रो(हांगकांग) लिमिटेड ने यह बताया है कि उनकी कीमत जीएनएफसी समेत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से तुलनीय है। इस वक्तव्य का कोई विधिक आधार नहीं है और कोवेस्ट्रो ने अपने दावों को सही साबित करने के लिए कोई इक्यू उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- xii. कोवेस्ट्रोने यह आरोप लगाया है कि शुल्क लगाने से एकाधिकार हो जाएगा क्योंकि जीएनएफसी एकमात्र उत्पादक है और वह भारतीय क्रेताओं के लिए सामग्री की उपलब्धता को सीमित कर देगा। इस तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है। जीएनएफसी

भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जो इस कंपनी को पाटन से बचाना आवश्यक बना देता है नहीं तो घरेलू बाजार में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व हो जाएगा, घरेलू उद्योग के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

- xiii. कोवेस्ट्रो ने यह आरोप लगाया है कि शुल्क लगाने से भारत में मांग-आपूर्ति में अंतर हो जाएगा। इस दावे का कोई आधार नहीं है। पाटनरोधी शुल्क वस्तुतः आयातों के विरुद्ध नहीं है। इससे पाटन के क्षतिकारी प्रभाव समाप्त होते हैं। मांग-आपूर्ति का अंतर, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग को पाटन से संरक्षण की मांग करने से नहीं रोकता है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे का अनेक जांचों में समाधान किया है और यह निरंतर पाया गया है कि मांग-पूर्ति का अंतर यदि कोई हो, पाटन को अनुमति देने का कारण नहीं हो सकता है।

61. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की तथ्यपरक जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसा कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती।

62. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iv) के साथ पठित पाटनरोधी नियम 11 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

63. प्राधिकारी द्वारा यहां किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण वस्तुतः विरोधी हितवद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग के भी विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। तथापि, हितवद्ध पक्षों द्वारा किए गए कतिपय विशिष्ट अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा नीचे ध्यान दिया गया है :

64. इस दलील के संबंध में कि निर्यातक की कीमत भारतीय बाजार में जीएनएफसी समेत अन्य आपूर्तिकर्ताओं से तुलनीय है, यह नोट किया जाता है कि इस विवरण से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए पाटन और क्षति के दावों का निरनुमोदन नहीं होता है और इसे निराधार विवरण माना जाना चाहिए।

65. इस दलील के संबंध में कि आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है और पीयूसी पर किसी पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार हो जाएगा, यह नोट किया जाता है कि यह अनुरोध कानूनी या वास्तविक रूप से बिल्कुल निराधार है। पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, को पाटन के व्यापार विकृतकारी प्रभावों को सही करने के लिए लगाया जाता है और नियमों किसी एकमात्र उत्पादक को पाटन से संरक्षण की मांग करने से वंचित नहीं करते हैं।

66. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से भारत में मांग पूर्ति में अंतर हो जाएगा क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने में असमर्थ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद के प्रभावित होने पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने के लिए पात्र होने के लिए देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है तथापि वास्तव में वर्तमान मामला उस क्षमता का है जिसे घरेलू उद्योग ने देश में मांग के स्तर तक का स्थापित किया है। यह भी नोट किया जाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाते हैं कि तो उनसे केवल पाटन का क्षतिकारी प्रभाव समाप्त होगा और उनमें क्षति या पाटन मार्जिन से आगे किसी संरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है और उससे आयात प्रभावित नहीं होंगे और उपभोक्ता तब भी संबद्ध देशों से अपाटित कीमतों पर आयात कर सकते हैं।

67. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अन्य संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर संबंधित नियमावली के अनुबंध II (iv) के अनुसार विचार किया है।

संचयी निर्धारण

68. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा

(ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।

69. प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि :

क) संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों में विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा आयातों की कुल मात्रा से अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक है।

ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल सीधे उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा बेची जा रही वस्तु के समान वस्तु हैं।

70. उक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संचयी आकलन करना उचित होगा।

ii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव**क. मांग और बाजार हिस्सा**

71. प्राधिकारी ने वर्तमान जॉच और इस अनंतिम जॉच परिणाम के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। प्राधिकारी ने भारत में आयातों पर डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आकड़ों के अनुसार सभी स्रोतों से भारत में पीयूसी के आयातों की मात्रा और मूल्य निर्धारित करने के लिए विचार किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

i) मांग

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
मांग	मी.टन	49,531	51,168	57,121	64,398
सूचीबद्ध	प्रवृत्ति	100.00	103.30	115.32	130.01
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	30,097	32,171	37,232	32,115
अन्य देशों से आयात	मी.टन	2,438	1,983	1,319	122
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	16,997	17,014	18,570	32,161
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा

72. विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तु के आयातों और भारतीय उत्पादक की संबद्ध वस्तु की बिक्री पर विचार करते हुए मांग निर्धारित की गई और भारत में इस मांग में संबद्ध आयातों, घरेलू उद्योग और अन्य आयातों के बाजार हिस्से की भी जाँच की गई और इस संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	%	34.32	33.25	32.51	49.94
अन्य देशों से आयात	%	4.92	3.88	2.31	0.19
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	60.76	62.87	65.18	49.87
भारतीय उत्पादकों से इतर की बिक्री	%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

73. उक्त तालिकाओं से यह देखा जाता है कि देश में उत्पाद की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई गई है और क्षति अवधि में उसमें काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार मांग में कोई गिरावट नहीं आई है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों का पीओआई के दौरान लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा था और इतने हिस्से को अधिक माना जाता है। इसी के साथ, अन्य देशों से आयातों के हिस्से में और गिरावट आई है और पीओआई के दौरान वे नगण्य थे।

ख. आयात मात्रा और संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा

74. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त सौदावार आयात आकड़ों के अनुसार संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जाँच की है। प्राधिकारी ने अनंतिम जाँच परिणामों के लिए उन पर भरोसा किया है। रिकार्ड में आयातों आकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से आयात मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक पाई गई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात मात्रा निम्नानुसार दी गई है : -

विवरण		इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
मात्रा	चीन जन. गण.	मी. टन	5,729	6,738	8,572	6,724
	जापान	मी. टन	8,017	9,190	12,322	8,913
	कोरिया गणराज्य	मी. टन	16,351	16,243	16,339	16,479
	संबद्ध देश कुल	मी. टन	30,097	32,171	37,232	32,115
	अन्य देश	मी. टन	2,438	1,983	1,319	122
	कुल आयात	मी. टन	32,534	34,154	38,551	32,237
आयातों में बाजार हिस्सा	चीन जन. गण.	%	17.61	19.73	22.23	20.86
	जापान	%	24.64	26.91	31.96	27.65
	कोरिया गणराज्य	%	50.26	47.56	42.38	51.12
	संबद्ध देश	%	92.51	94.19	96.58	99.62
	अन्य देश	%	7.49	5.81	3.42	0.38

75. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तु के आयात प्राथमिक रूप से संबद्ध देशों से हो रहे थे। संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा समग्र रूप से बढ़ा है और वह पूरी क्षति अवधि के दौरान भारत में कुल आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। वास्तव में, संबद्ध देशों से आयातों का पीओआई के दौरान भार में कुल आयातों का लगभग 99.62 प्रतिशत हिस्सा रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पाद की मांग का काफी बड़ा हिस्सा बने रहे। संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में समग्र रूप से और क्षति अवधि के दौरान और पीओआई के दौरान भारत में मांग के हिस्से के रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात जो आधार वर्ष में 30097 मी.टन थे पीओआई के दौरान बढ़कर 32115 हो गए और पीओआई के दौरान भारतीय मांग में उनका हिस्सा 49.87 प्रतिशत था। घरेलू मांग में पाटित आयातों का भारी हिस्सा और संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि बिलकुल स्पष्ट है।

ग) उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों का हिस्सा

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	30,097	32,171	37,232	32,115
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी. टन	17,875	16,317	23,737	45,680
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात	%	168.38%	197.17%	156.85%	70.31%

77. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में कुल भारतीय उत्पादन से काफी अधिक रहे हैं जो पीओआई में 70.31 प्रतिशत थे। यद्यपि घरेलू उद्योग का उत्पादन आरंभिक दो वर्षों में काफी अधिक नहीं था तथापि 2014-15 के दौरान और पीओआई के दौरान काफी क्षमता वृद्धि की गई। पीओआई के दौरान बढ़े हुए उत्पादन आकड़ों के साथ भी संबद्ध देशों से आयात पूरी क्षति अवधि और पीओआई के दौरान भी भारत में उत्पादन के संबंध में काफी उच्च स्तर पर थे और यह उच्च स्तर देश में उत्पाद की मांग के संबंध में भी स्पष्ट है। इस प्रकार संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और वह भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी काफी उच्च स्तर पर रहे हैं।

iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

78. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है :

"नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों का अत्यधिक ह्रास हुआ है अन्यथा कीमत वृद्धि में रुकावट आई है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती।"

79. यह जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद के पाटित आयातों से पर्याप्त मात्रा में कीमतों में गिरावट आई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव कीमतों में पर्याप्त मात्रा में अन्यथा गिरावट के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकते हैं, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत में गिरावट और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सीओपी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना नीचे समुचित खंडों में संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है।

(क) कीमत में कटौती

80. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुँच कीमत की तुलना की है। इस संबंध में उत्पाद के पहुँच मूल्य और सभी छूटों और करों को मिलाकर व्यापार के उसी स्तर पर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग

की कीमतें कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित की गई थी। घरेलू कीमतों और कीमतों में कटौती का मार्जिन नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.	जापान	कोरिया गण.	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु./किग्रा	123.92	111.57	110.05	113.37
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक	ऋणात्मक

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से कीमत कटौती ऋणात्मक रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों का पहुँच मूल्य कीमत पर ह्रासकारी और न्यूनकारी दोनों रहा है जिसमें घरेलू उद्योग को निरंतर अपनी कीमतों को आयातों के पहुँच मूल्य के बराबर करने के लिए कम करना पड़ा है। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करके आयातों का उत्तर नहीं देता है तो वह अपने ग्राहक गंवा देगा और क्षति और अधिक होगी। वर्तमान मामले के तथ्यों में घरेलू उद्योग पीयूसी को उसकी उत्पादन लागत से कम दर पर बेच रहा है और घाटा उठा रहा है।

(ख) कम कीमत पर बिक्री

82. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री होने की भी जांच की है। इस प्रयोजन के लिए अनुबंध III के अनुसार पीओआई के लिए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी की आयातों की पहुँच कीमत के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की भारित औसत एनआईपी की आयातों की भारित औसत पहुँच कीमत के साथ तुलना की गई है, जो यह दर्शाती है :

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.	जापान	कोरिया गणराज्य
क्षतिरहित कीमत	रु./किग्रा	***	***	***
पहुँच कीमत	रु./किग्रा	123.92	111.57	110.05
कम कीमत पर बिक्री	रु./किग्रा	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	05-20	20-30	20-30

83. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से काफी कम है जिससे कम कीमत पर बिक्री का पता चलता है।

ग) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

84. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में दबाव पड़ रहा है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोक रहा है, जो अन्यथा पर्याप्त मात्रा में होती, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान कीमत लागतों व कीमतों में बदलावों पर विचार किया है। स्थिति नीचे सारणी में दर्शाई गई है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन लागत	रु/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	111.04	136.86	122.79
बिक्री कीमत	रु/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	81	60
पंहुच मूल्य (संबद्ध देश)	रु/किग्रा.	166.73	162.17	153.64	113.37
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97.26	92.15	68.00

85. उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि उत्पादन लागत में आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से पीओआई में 122.79 बिंदुओं की वृद्धि हुई है जबकि बिक्री कीमत में आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं की तुलना में 60 सूचीबद्ध बिंदुओं का बदलाव हुआ है जो पाटित कीमतों के कारण कीमतों पर भारी कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव को दर्शाता है क्योंकि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। यह स्पष्ट है कि आयातों की पंहुच कीमत से कीमत ह्रास/न्यूनीकरण हुआ और उससे कम कीमत पर बिक्री के अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री प्राप्ति पर गंभीर कीमत प्रभाव पड़ा है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

86. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है :

घ. क्षमता और क्षमता उपयोग

87. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
क्षमता मी.टन	मी.टन	14,000	14,000	64,000	64,000
उत्पादन	मी.टन	17,845	16,317	23,737	45,680
क्षमता उपयोग	%	127.68	116.55	37.09	71.38

88. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने 2014-15 के दौरान क्षमता में वृद्धि की और तत्पश्चात क्षमता पीओआई के दौरान भी वही रही। यद्यपि क्षमता उपयोग में गिरावट क्षमता में वृद्धि के कारण हो सकती है, उक्त आकड़ों में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि क्षमता उपयोग 71.38 प्रतिशत पर बना रहा था।

89. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि पाटित आयातों के कारण वे ईष्टतम क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य नहीं कर सके हैं और क्षमता के इस कम उपयोग के समय देश में संबद्ध वस्तु की मांग में भारी वृद्धि हुई थी। घरेलू उद्योग द्वारा भारी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता बढ़ाई गई थी, तथापि इस वृद्धि से घरेलू उद्योग को मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार समग्र उत्तम कार्यनिष्पादन हासिल करने में मदद नहीं मिली क्योंकि संबद्ध देश से भारी मात्रा में पाटित आयात मौजूद थे। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यदि पाटित आयातों का बाजार में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं होता तो घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग का काफी बेहतर स्तर प्राप्त कर सकता था जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को क्षमता उपयोग में वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।

ड.) उत्पादन

90. घरेलू उद्योग का उत्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादन	मी.टन	17,875	16,317	23,737	45,680
मांग	मी.टन	49,531	51,168	57,121	64,398
मांग के संबंध में उत्पादन	%	36.09	31.89	41.56	70.93

91. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में पीओआई तक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादन में वृद्धि को एकमात्र मापदंड न माना जाए क्योंकि क्षमता उपयोग काफी निचले स्तर पर रहा है जो पीओआई के दौरान वांछनीय स्तर से 71.38 प्रतिशत रहा। यदि पाटन नहीं होता तो पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग स्वयं संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा कर सकता था।

92. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यद्यपि क्षमता और उत्पादन में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है तथापि संबंधित कीमत संबंधी मापदंडों में तेजी से गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है जिससे लाभ नहीं हुए जो क्षमता और उत्पादन जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग द्वारा हासिल किए जाने चाहिए थे।

च. बिक्री मात्रा और बाजार हिस्सा

93. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू बिक्री	मी.ट.	16,997	17,014	18,570	32,161
मांग	मी.ट.	49,531	51,168	57,121	64,398
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	34.32	33.25	32.51	49.94

94. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। पीओआई के दौरान बिक्री में यह प्रवृत्ति पीओआई के दौरान क्षमता और उत्पादन में विकास के समनुरूप है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यद्यपि पीओआई तक बिक्री मात्रा बढ़ी है तथापि क्षमता उपयोग वांछित स्तर से कम रहा है और पीओआई के दौरान बाजार हिस्से के लगभग 50 प्रतिशत पाटित आयातों के पास रहा है जो घरेलू उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है परंतु पाटित आयातों के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस प्रकार मात्रा के अनुसार पीओआई के दौरान बिक्री की स्थिति में क्षति और स्थिर वृद्धि के संकेत भी दिखे हैं। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान संबद्ध कीमत संबंधी मापदंडों में तेजी से गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे भी हुए हैं।

95. इसके अलावा, यद्यपि बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है तथापि उसे आयातों की पंहच कीमत के बराबर कीमत को समायोजित करके ही प्राप्त किया जा सकता था। सार रूप में, बिक्री मात्रा में वृद्धि से आधार रूप में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से भारी मात्रा में पाटित आयात आ रहे थे। बिक्री की स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि का विवेक भी घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में नहीं दिखा है जो वित्तीय मापदंडों में प्रदर्शित होता है। मात्रा संबंधी मापदंडों में वृद्धि कार्यनिष्पादन पर स्थिर लागत के कुछ प्रभाव से निष्क्रिय हो गई परंतु वह पीओआई के दौरान भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कार्यनिष्पादन में समग्र सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

96. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य मात्रा संबंधी मापदंडों में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। तथापि जैसा नोट किया गया है संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्सा पीओआई के दौरान काफी उच्च स्तर पर रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाटित आयातों से पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की वास्तविक और संभावित बिक्री मात्राओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा था। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि बिक्री मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई परंतु घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता थी और उसे बिक्री मात्रा को बनाये रखने के लिए और बढ़ते हुए स्टॉक के दबाव को कम करने के लिए कीमतों में और कमी करनी पड़ी।

ख. मालसूची

97. घरेलू उद्योग के पास औसत स्टॉक के रूप में मालसूची की स्थिति निम्नानुसार है :

	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
औसत स्टॉक	मी.टन	748	776	1,625	2,107

98. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है और पीओआई के दौरान वह उच्चतम स्तर पर रही है। यह भी नोट किया जाता है कि मालसूची में ऐसे समय वृद्धि जब मांग और उत्पादन में उसी अवधि में वृद्धि हो रही है घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार मालसूची की स्थिति पर पाटन का प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट है।

ज. लाभ/हानि

99. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
लाभ	रु/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	48.37	(89.46)	(131.64)
लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	48.42	(97.74)	(249.08)

100. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में विकृति आई है और घरेलू उद्योग को पीओआई और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारी घाटा होने लगा था। घरेलू उद्योग पहले लाभ कमा रहा था। यहां उक्त से नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत से उसी अवधि के दौरान घरेलू कीमत पर कीमत ह्रास/न्यूनीकरण और कम कीमत पर बिक्री प्रभाव पड़े हैं। ऐसी पहुंच कीमत का प्रभाव घरेलू उद्योग की वित्तीय घाटे की स्थिति से स्पष्ट है।

झ. नियोजित पूंजी पर आय

101. नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है :

	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	(6)	(21)

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय में क्षति अवधि में भारी गिरावट आई है और पीओआई में वह दो पूर्ववर्ती वर्षों से काफी ऋणात्मक हो गई है। यह प्रवृत्ति लाभ से तुलनीय है। घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि पाटित आयातों से भारी कीमत दबाव के कारण लाभप्रदता और आरओसीई में ऐसी गिरावट आई है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के बचे रहने के लिए अनिवार्य है। यह भी बताया गया है कि बढ़ते हुए वित्तीय घाटों को आगे जाँच होने तक अंतरिम उपायों से पाटित आयातों पर रोक लगा कर ही नियंत्रित किया जा सकता है।

ब. नकद प्रवाह

103. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकद प्रवाहकी स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जाँच करने के लिए नकद लाभों की प्रवृत्ति की जाँच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ संबंधी सूचना नीचे तालिका में दी गई है :

	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
नकद लाभ	लाख रुपये	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	(53)	(149)

104. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभ में क्षति अवधि में कमी आई है और पीओआई में आधार वर्ष की तुलना में वह ऋणात्मक हो गया है।

ट. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

105. लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा और प्रतिस्पर्द्धी प्रतिस्थापन, यदि कोई हों, की पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करते हैं की जाँच की गई है। यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जाँच में याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जो परस्पर अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त कर देता है। पीओआई के दौरान लागत संरचना में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तथापि, संबद्ध आयातों की पंहुच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और उचित विक्री कीमत से कम है। यह निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि परस्पर प्रतिस्पर्द्धा या लागत संरचना में किसी अन्य बदलाव के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है।

ठ. उत्पादकता

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी उत्पादन के समान ही प्रवृत्ति रही है। प्रतिदिन उत्पादकता वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है और यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिदिन उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का कारण है।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	87.40	28.94	55.69
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	91.28	132.80	255.56

107. यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी उत्पादकता इस मामले के तथ्यों का संगत कारक नहीं है क्योंकि पीओआई में क्षमता में और कर्मचारियों के स्तर में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रतिदिन उत्पादकता के मुकाबले उत्पादकता में संकेतात्मक प्रवृत्ति है और उसकी जाँच की गई है।

ड. रोजगार और मजदूरी

108. रोजगार स्तर में क्षमता और उत्पादन जैसी ही प्रवृत्ति ही रही है। मजदूरी प्रति किग्रा. में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि मजदूरी में वृद्धि सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप है और कंपनी द्वारा प्रदत्त मजदूरी में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि मजदूरी और रोजगार से घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि

उनके पास और रोजगार सृजित करने की क्षमता है बशर्ते संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाकर व्यापार की उचित स्थिति बनाई जाए।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	104.44	458.89	458.89
मजदूरी	रु/किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	208	185

ढ वृद्धि

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मापदंडों के अनुसार ऋणात्मक है। अनेक मापदंडों में घरेलू उद्योग की ऋणात्मक वृद्धि स्पष्ट है जब उत्पाद की बाजार मांग में निरंतर वृद्धि हुई है जो अन्य बातों के साथ-साथ दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को भारी प्रतिकूल कीमत प्रभाव के साथ पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण ऐसी सकारात्मक बाजार स्थिति का लाभ लेने से रोका गया है।

ण. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तथापि, इन निवेशों और क्षमता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में काफी कमी आई है और यदि संबद्ध वस्तु के पाटन का समाधान नहीं किया तो आगे निवेश प्रतिकूलतः प्रभावित होंगे।

त. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

111. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं और पाटन का मार्जिन काफी अधिक है।

छ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

112. क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों की जाँच से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में सापेक्ष अर्थों में काफी वृद्धि हुई है। आयातों में भारत में उत्पाद आयातों में भारत में पीयूसी की खपत और उत्पादन के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार से आयातों में सापेक्ष अर्थों में और भारत में उत्पादन व खपत के संदर्भ में, दोनों में वृद्धि हुई है।

113. आयातों से कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यद्यपि उत्पादन लागत में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट हुई है और घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पा रहा है और पीओआई में भारी घाटा उठा रहा है। इस प्रकार पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास/न्यूनीकरण कर रहे हैं और कीमत वृद्धि को रोक रहे हैं।

114. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्पाद की मांग और घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य मात्रात्मक मापदंडों में पीओआई के दौरान सुधार हुआ है। तथापि घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता में अनुपातिक सुधार नहीं कर पाया है क्योंकि पाटित आयातों का बाजार में काफी हिस्सा बना हुआ है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होने लगा। यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा को नहीं बढ़ा सका तथापि उससे लाभप्रदता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि बिक्री मात्रा में वृद्धि को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पाटित कीमतों के बराबर रखकर प्राप्त किया गया था।

115. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है और घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान वित्तीय घाटा उठाता रहा है। नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ दोनों पीओआई के दौरान नकारात्मक रहे हैं। इसके अलावा लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय आदि जैसे अधिकांश मापदंडों के संबंध में वृद्धि नकारात्मक रही है और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाती है।

116. ऐसे सभी कारकों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का सामना करना पड़ा है।

ज. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

117. प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य कारक, जो पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध हैं, ने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दिया है। संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की गई है, जो इस प्रकार है :

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

118. संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से आयात मात्रा के संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति की आशंका हो। अन्य देशों से आयात कुल 0.5 प्रतिशत हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य देशों से आयात क्षति पहुंचा रहे हैं।

(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा

119. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का एक बाजार है जिसमें संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और समान अनुप्रयोगों/अंतिम प्रयोगों के लिए प्रयुक्त होती हैं। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से क्षति होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) मांग में संकुचन और खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की मांग में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कारण नहीं हो सकता।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

121. किसी भी हितबद्ध पक्ष ने प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी खास परिवर्तन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

122. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात के व्यौरे निम्नानुसार हैं :

अवधि	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
निर्यात	मी.टन	120	-	2,714	14,947
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	100	429

2. घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभव महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण है। वास्तव में घरेलू उद्योग के निर्यातों में पीओआई के दौरान वृद्धि हुई है। अतः निर्यात कार्य निष्पादन में संभावित गिरावट किसी क्षति का कारण नहीं है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

(छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

124. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के निष्पादन के लिए किए गए आकलन पर प्रभाव द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

झ. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

125. घरेलू उद्योग के निष्पादन का क्षति अवधि के दौरान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तव में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण गिरावट आई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधार पर सिद्ध होता है :

- क) संबद्ध वस्तुओं के आयात में जांच की समग्र अवधि के दौरान सापेक्ष अर्थों में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है इसके अलावा आयातों की पंहुच कीमत में भी क्षति अवधि से पीओआई के दौरान भारी गिरावट आई है।
- ख) संबद्ध वस्तुओं के आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ग) भारत में पाटित आयातों के बाजार हिस्सा पीओआई के दौरान लगभग 50 प्रतिशत बना रहा है जो पर्याप्त प्रतिशत है और वह भी जब संबद्ध वस्तु की मांग भारत में बढ़ रही है। यह इस कारण से है कि आयातों ने मांग पर तेजी से कब्जा कर लिया है।
- घ) घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि नहीं कर पाया। घरेलू उद्योग के पास मांग में वृद्धि के बावजूद पीओआई में भारी अप्रयुक्त क्षमता थी।
- ङ) घरेलू उद्योग की माल-सूची बढ़ रही है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद अपनी बिक्रियों में वृद्धि नहीं कर पाया। आयातों ने भारत में मांग पर तीव्रता से कब्जा कर लिया है।
- च) भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण कीमतों में काफी गिरावट और दबाव पड़ रहा है।
- छ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और लगी पूंजी पर प्रतिफल पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। यदि इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग 2013-14 तक लगी पूंजी पर पर्याप्त लाभ और प्रतिफल प्राप्त करता रहा था। तथापि, विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान लाभ और प्रतिफल में भारी नुकसान और नकारात्मक स्थिति शुरू हो गई।

126. उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों में वृद्धि के कारण वास्तव में क्षति का सामना करना पड़ रहा है। संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक सशक्त कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ज. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

127. प्राधिकारी ने यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार निर्धारित क्षतिरहितकीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पंहुचकीमत के साथ की गई है जो निम्नानुसार है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	क्षति रहित कीमत - अम.डा./ किग्रा.	पंधुच कीमत - अम.डा./ किग्रा.	क्षति मार्जिन - अम.डा./ किग्रा.	क्षति मार्जिन - %	क्षति मार्जिन रेंज - %
1	चीन जन. गण.	कोई	कोई	***	***	***	***	10-20
2	जापान	कोई	कोई	***	***	***	***	20-30
3	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि.	***	***	***	***	30-40
4	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	एवरलाईट कोरिया कं. लि.	***	***	***	***	20-30
5	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	आईएमएस कार्पोरेशन	***	***	***	***	20-30
6	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. और टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी, यूएई	***	***	***	***	30-40
7	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	क) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. ख) एवरलाईट कोरिया कं. लि. ग) आईएमएस कार्पोरेशन घ) टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी,	***	***	***	***	30-40
8	कोरिया गणराज्य	बीएसएफ कं. लि.	बीएसएफ कं. लि.	***	***	***	***	30-40
9	कोरिया गणराज्य	उक्त क्र. से. 3 से 8 के उत्पादकों से इतर कोई अन्य उत्पादक	उक्त क्र. से. 3 से 8 के निर्यातकों से इतर कोई अन्य निर्यातक	***	***	***	***	35-45

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

128. उठाये गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों जैसे इस प्रारंभिक जाँच परिणाम में दर्ज हैं की जाँच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- i. विचाराधीन उत्पाद का भारत को संबद्ध देशों से निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- ii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- iii. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

129. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ कम होगा, घरेलू उद्योग का ह्रास होने से रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग मिलेगा। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से उपभोक्ताओं इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से ईरान से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होगा और उपभोक्ताओं इस संबद्ध वस्तु की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अभी भी इस उत्पाद की आपूर्ति के अनेक स्रोत बनाए रख सकते हैं।

ड. सिफारिश

130. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध और अनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- क. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

131. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी पक्षकारों को इसके संबंध में अधिसूचित किया गया था। निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में पाटन, क्षति और तत्संबंधी कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करके और पूरी करने पर तथा पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को एक सकारात्मक पाटन मार्जिन और सामग्री क्षति प्रमाणित करते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति को दूर करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर नीचे वर्णित तरीके और ढंग से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

132. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में बराबर समान अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखितानुसार राशि के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	कोई	कोई	0.26	किग्रा.	अम. डा.
2	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	चीन जन. गण.	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.26	किग्रा.	अम. डा.
3	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	कोई	0.26	किग्रा.	अम. डा.
4	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	जापान	जापान	कोई	कोई	0.14	किग्रा.	अम. डा.
5	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	जापान	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.14	किग्रा.	अम. डा.
6	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	जापान	कोई	कोई	0.14	किग्रा.	अम. डा.
7	29291020	टोलीन डि-आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	हानवा फाइन कैमिकल कार्पोरेशन	क) पी एंड वाई इंटरनेशनल कं. लि. ख) एवरलाईट कोरिया कं. लि. ग) आईएमएस कार्पोरेशन घ) टीजे एएल मुलूक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी,	0.17	किग्रा.	अम. डा.

8	29291020	टोलीन डि- आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	बीएएसएस कं. लि.	बीएएसएस कं. लि.	0.31	किग्रा.	अम. डा.
9	29291020	टोलीन डि- आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य	उक्त क्र. सं. 7 और 8 में उल्लिखित से इतर कोई समूह		0.40	किग्रा.	अम. डा.
10	29291020	टोलीन डि- आइसोसायनेट	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	कोई	0.40	किग्रा.	अम. डा.
11	29291020	टोलीन डि- आइसोसायनेट	कोरिया गणराज्य	पाटनरोधी शुल्क के अधीन से इतर कोई देश	कोई	कोई	0.40	किग्रा.	अम. डा.

ढ. आगे की प्रक्रिया

133. प्रारम्भिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :-

- क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जाँच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी के द्वारा उन्हें प्रासंगिक समझे जाने पर अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया जाएगा।
- ख) निर्यातक, आयातक, आवेदक और संबद्ध माने गए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा अलग से लिखा जा रहा है, जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इन जाँच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रकट कर सकता है।
- ग) प्राधिकारी जरूरी समझी गई सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।
- घ) प्राधिकारी अंतिम जाँच परिणामों को अधिसूचित करने से पहले हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए मौखिक सुनवाई आयोजित कर सकते हैं।
- ङ) अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पूर्व, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2017

Preliminary Findings

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Toluene Di- Isocyanate (TDI)’ originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

No.14/36/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time [hereinafter also referred to as the Act] and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, [hereinafter also referred to as the Rules], as amended from time to time, thereof;

2. Whereas M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as “the petitioner” or “the applicant”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and Rule *supra* for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of “Toluene Di- Isocyanate” (TDI in short) (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries) alleging dumping of subject goods from subject countries and consequent injury to the domestic industry.
3. And whereas the Authority on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No.14/36/2016-DGAD dated 05.10.2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject anti-dumping investigation in accordance with the sub Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;
 - i. Preliminary scrutiny of the application showed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
 - ii. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of rule 5 *supra*.
 - iii. In addition to the provisions of sub-rule (5) of Rule 5 *supra*, the Government of Korea RP was informed through its Embassy in India about the receipt of the subject application as per provisions of Article 2.14 of Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and Korea RP.
 - iv. Post initiation, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules. Necessary extensions to file such submissions wherever warranted have also been permitted by the Authority.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
 - a) Yantai Juli Fine Chemical Co., Ltd,
China PR.

- b) Changzhou Dahua Group Co., Ltd,
China PR.
 - c) Shanghai BASF Polyurethane Co., Ltd,
China PR.
 - d) Bayer Material Science (China) Co., Ltd,
China PR.
 - e) Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes,
Japan.
 - f) Nippon Polyurethane Industry Co., Ltd,
Japan.
 - g) Hanwha Fine Chemical Co., Ltd.
Korea RP
 - h) OCI Corporation/OCI Company Ltd.
Korea RP
 - i) BASF Company Ltd.
Korea RP
- vii. In response to the initiation notification and intimation, the following exporters / producers from subject countries have responded to the Authority by filing Exporter Questionnaire Response;
- a) Hanwha Fine Chemical Corporation, Korea RP
 - b) TJ AL Mulook General Trading LLC, UAE
 - c) P & Y International Co. Ltd, Korea RP
 - d) IMS Corporation, Korea RP
 - e) Everlite Korea Co., Ltd, Korea RP
 - f) BASF Company Ltd, Korea RP
- viii. Apart from the above companies, following companies from China PR also shown their interest to participate in the investigation though they claimed not to have exported the subject goods to India during the POI;
- a) Wanhua Chemical Group Co., Ltd
 - b) Cangzhou Dahua Holding Co., Ltd
- ix. Following exporters also filed certain submissions following the initiation;
- a) Covestro (Hong Kong) Limited
 - b) Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes INC
- x. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information;
- 1. Sheela Group Co.,
 - 2. Tirupati Foam
 - 3. Kurlon Ltd.
 - 4. Springwell Mattresses
 - 5. Sunrise Foam Product Pvt Ltd.
 - 6. M H Polymers
 - 7. Pyarelal Foam (South)
 - 8. Jindal Foam
 - 9. Allied Foam
 - 10. DuraPuff
 - 11. Fancy Foam
 - 12. Hindustan Polyfoam
 - 13. Shree Malani Foams
 - 14. Prime Comforts
 - 15. Springfeel Polyurethanes
 - 16. Aadi Polymers
- xi. In response, following importers/users have responded by filing Importer Questionnaire responses;
- a) Sheela Foam Ltd

- xii. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xiii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry or not.
- xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xv. On site verification of the information provided by the domestic industry were conducted at this preliminary stage to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, is relied upon for the purpose of this provisional finding.
- xvi. The Authority has considered 1st April, 2015 to March 31st (12 months) as the POI so as to undertake analysis on the most recent data. Thus, investigation was carried out for the period starting from 1st April 2015 to 31st March 2016(POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, however, covered the periods Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the period of investigation.
- xvii. Import information as per secondary sources (IBIS) has been provided in the application by the applicant and the same has been relied upon at the initiation stage. However, the Authority has relied upon the transaction wise import data as collected from DGCI&S for the purpose of volume and value of subject goods into the country for the previous years and POI for the purpose of this provisional finding.
- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present provisional finding on the basis of the facts available.
- xix. ***In this provisional finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. Exchange rate for conversion of US\$ to Rupees considered for the POI is Rs 65.91 per 1 US\$ as per customs data.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 5. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Toluene Di- Isocyanate" (TDI) originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.
- 6. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration.
- 7. TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc., packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.
- 8. TDI being an organic chemical is categorised under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under subheading 29291020 which pertains to Toluene di-isocyanate. However, as submitted by the applicant, this heading includes certain grades other than isomers (80:20) hence the classification is indicative only. It has also been claimed by the applicant that the imports of the subject goods have been reported under some other subheadings also such as 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 and 39095000. An examination of the import data as per DGCI&S shows that imports during POI were primarily under subheading number 29291020 and there were substantial imports under subheading 29291010 and 29291090 also. Hence, the Customs classification is

treated as indicative only and in no way binding on the scope of the PUC in the investigation and any measures to be recommended to be imposed, if any.

9. There have not been any submissions made by any of the responding interested parties vis-à-vis the definition and scope of the PUC, except one exporter, namely Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc (MCNS). MCNS sought clarifications from the Authority whether two products namely "TM" and "MT" are included/excluded in the scope of PUC or not. It has been submitted by MCNS that TM is a mixture of 50% or more of TDI and polymeric MDI (Polymethylenepolyphenyl/polyisocyanate or PMDI). Further, MT is a mixture of less than 50% of TDI and modified monomeric MDI, 4,4'- (Diphenyl methaneisocyanate). It has also been submitted by MCNS that there exists a vast difference in the chemical composition of TDI and TM/ MT and in fact TDI is used in the production/manufacturing process of TM and MT. After examining the submissions of MCNS, the Authority notes that the definition and scope of PUC is clearly provided in the initiation notification and also in this provisional finding regarding the PUC. Thus, PUC fulfilling the definition herein above alone shall come under the ambit and scope of present investigation and not any other products.

LIKE ARTICLE

10. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".

11. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules.
12. The Authority has examined the claims and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. In view of the above, the Authority provisionally holds that the products manufactured by the Applicant constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject countries within the meaning of Rule 2 (d) of the AD Rules.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

13. The Application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited as the domestic industry.
14. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject good in India. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production; in fact 100% share of total domestic production.
15. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under;
"(2) (b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"
16. It is noted that the application based on which the present anti-dumping investigation is initiated has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited as the "domestic industry" concerning the subject goods in India. As per the claims of the applicant, M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited is the sole producer of the subject goods in India. It is also noted that there are not any rival submissions on the aspect of domestic industry and standing filed by any of the opposing interested parties.

17. None of the interested parties have made any submission with regard to the scope and standing of the domestic industry. The applicant however submitted that they are the sole producer of the subject goods in India and qualifies to be treated as the “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) for the purpose of present investigation.
18. Since the production of the applicant accounts for “a major proportion” in the total production of the subject goods in India [in fact 100%], the Authority holds that the applicant satisfies the standing criteria under Rule 5(3) and constitutes domestic Industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. CONFIDENTIALITY

19. There haven't been any submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality aspect.
20. Certain submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality and disclosure of information and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. Excessive Confidentiality in submissions is adopted by responding producers/exporters and importers. The NCV version of the EQ Responses and IQ Responses do not permit any reasonable understanding of the claims of such parties vis-à-vis dumping and the detail of import that have been made in the country by such responding parties.
 - ii. NCV versions of the documents are provided in a manner restraining the domestic industry from making any evaluation of the same.
 - iii. The following basic information provided by the producer/exports/importers respectively cannot be claimed as confidential;
 - a. Information on total volume of exports/imports from subject countries,
 - b. Average price of imports from subject countries,
 - c. Holding Company details and also the name of the concerned producers where exporters/traders have filed the response. In fact, none of the exporters/traders participating have disclosed the names of the respective producers name whose materials have been exported by such parties.
 - iv. While the rules requires the parties providing information on a confidential basis to furnish non-confidential summary thereof, the responding parties have resorted to a methodology convenient to them and literally restricted the petitioner from gauging the factual position with regard dumped imports made by them. Excessive confidentiality adopted by the responding parties also contravenes the findings of the Appellate Body in European Communities-Anti-Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS 397/AB/R dated 15th July, 2011) wherein the Appellate Body has interpreted Articles 6.5 and 6.5.1 of the Anti-dumping Agreement concerning confidentiality.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

21. It is noted that none of the responding parties have filed any submission to dispute the confidentiality on certain information claimed by the domestic industry. However, there have been certain submissions made by domestic industry on the confidentiality claims of the responding parties. Various submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality/disclosure of information and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

22. With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

- (2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is*

not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. Various discussions in this provisional finding are self-explanatory on the other contentions of the domestic industry on confidentiality aspect.

E. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

a) Market Economy Treatment

24. The present investigation has been initiated on 5.10.2016 and it was open for the producers/exporters from China PR in the present investigation to rebut the NME presumption for the purpose of normal value determination. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR (in the present case) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:
- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
25. It is noted that none of the producers/exporters who have exported the subject goods to India during the POI have responded to the Authority in the present investigation by filing the required EQ Response and MET Response. Thus, the presumption of NME vis-à-vis China PR stands un-rebutted in the present investigation by the Chinese producer/exporters.

Submissions made by interested parties on MET

26. It is noted that there has not been any specific submissions concerning market economy, normal value, export price and dumping margin made by the producers/exporters/importers/other interested parties. The submissions concerning market economy, normal value, export price and dumping margin made by the domestic industry are as follows;
- a. China PR should be treated as Non Market Economy country for the purpose of present investigation and Normal Value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7.
 - b. Chinese producers have been denied MET status in several investigations including recently concluded investigations by both Indian Authority and other countries like EU, USA, Australia etc as a part of various anti-dumping investigations by treating China PR an NME country.
 - c. MET status can be given only in the event of fulfilment of all the MET conditions by the responding producers/exporters and not otherwise. Thus, requirements of para 8 (3) of Annexure I of AD rules has to be fulfilled holistically to obtain MET status.

- d. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
- e. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values. The expression “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.
- f. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establishes that their books are audited in line with international accounting standards. Market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).
- g. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.
- h. The onus is on the responding Chinese producer/exporters to establish that they are operating under market economy conditions after satisfying all the conditions mentioned in AD Rules.
- i. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected, irrespective of the fact that the other companies of the group involved in production or sale of the product under consideration have filed the response.
- j. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been fully transparent and completely established through documentary evidence.
- k. There are not any cooperating producers/exporters in the present investigation who have rebutted the presumption of NME status by filing all relevant information as per MET Questionnaire. China PR should be treated as Non Market Economy country based on this fact alone.
- l. The applicant has submitted normal value and dumping margin as per the available information and methods permissible specified in the AD Rule and relevant annexure to the rule. Details of such calculations are provided in the NCV application which is elaborate and contains all essential specifics. The Authority may rely on such information all practical purposes in this investigation in case the concerned producer/exporters fail to meaningfully cooperate.
- m. The provisions of China Accession Treaty have no implications on the present case since the present case is initiated on 5.10.2016 and the POI selected is April 2015- March 2016.
- n. It is evident from the EQ Response filed by HFCC that the entity namely Hanwha Fine Chemical Corporation (HFCC) merged into a business division of Hanwha Chemical Corporation (HCC) on 29th February, 2016. However, the EQ Response is filed by providing details of HFCC as the entity which has no legal or factual justification.
- o. The questions in the entire EQ Response should have been answered by treating HCC as the entity with the given facts and not HFCC which ceased to exist on 29th February, 2016. In this scenario, the Authority should the entire response by HFCC treating them as incorrect and incomplete and is not of any pursuable legal tenability.
- p. All the questions are answered in the concerned Response by treating HFCC as the relevant entity. For example list of shareholders, details of factories involved etc of HFCC is provided whereas what is relevant as can be seen from the facts disclosed is replies to these questions by HCC as the entity and not HFCC which ceased to exist on 29.2.2016 well within the POI. The incorrect and inappropriate answers provided cannot be rectified at this juncture and the Response as such should be rejected.
- q. It can be noted that any response by HCC would have to be significantly different from that of HFCC and the examination of EQ Response filed by HFCC instead of HCC would not help the Authority to conduct any examination of dumping. HFCC ceased to exist on 29.2.2016 and the entity relevant to have filed EQ Response in the given scenario is HCC and HCC did not file any EQ Response in effect.

- r. Entire questions in the EQ Response should have been answered by HCC and HCC alone could have sought individual margin and not HFCC. In any case, even if an individual margin is given to HFCC, it is of no use as HFCC is not in existence.
- s. It is submitted by HCC in the NCV repose that there is one channel involved in the export of PUC into India, however, the name of such exporter is not provided. It needs to be seen whether such exporter involved have filed exporter response.
- t. HCC has resorted to excessive confidentiality and did not disclose the name of exporter in the channel. How can a name of the exporter be treated as confidential? Can the Authority treat name of an exporter as confidential in the duty table if at all an individual margin is provided? Thus, basic information is kept as confidential in absolute disrespect to the confidentiality provisions and such claim of confidentiality is absolutely bogus which should be rejected by the Authority.
- u. It is evident from the EQ Response filed TJ AL Mulook that TJ AL Mulook is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by TJ AL Mulook?
- v. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by TJ AL Mulook cannot be considered for individual margin determinations.
- w. It is evident from the EQ Response filed P & Y International Co. Ltd that P & Y International Co. Ltd is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by P & Y International Co. Ltd?
- x. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by P & Y International Co. Ltd cannot be considered for individual margin determinations.
- y. It is evident from the EQ Response filed IMS Corporation that IMS Corporation is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by IMS Corporation?
- z. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by IMS Corporation cannot be considered for individual margin determinations.
- aa. It is evident from the EQ Response filed Everlite Korea Co., Ltd that Everlite Korea Co., Ltd is only an exporter/trader and not a producer of subject goods. However, there is no disclosure in the EQ Response as to who all is the producer/s of the subject goods exported by Everlite Korea Co., Ltd?
- bb. Without cooperation by way of full EQ Response by the corresponding producer, response filed by Everlite Korea Co., Ltd cannot be considered for individual margin determinations.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

27. The Authority notes that the relevant provisions laid down under Annexure I to the Antidumping Rules with regard to “Market Economy Treatment” are as follows;

[8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country.

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph].”

[(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti dumping investigations, by a country which is a member of the World Trade Organization].”

28. The Authority also notes that Article 15 of China’s Accession Protocol provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a*

particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

29. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraphs shall expire in 15 years from the date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th December, 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2015 to March, 2016. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevailed in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
30. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules. However, there are not any participation by producers/exporters from China PR who have exported the subject goods to India during the POI, therefore, it is noted that the presumption of NME which was prevalent during the POI is not rebutted as provided in the Rule. It is also noted that since investigation has been initiated on 5.10.2016 and the POI determined for the present investigation is April 2015-March 2016, the provisions of China Accession Treaty which says that WTO Members could use an NME antidumping methodology till December 11, 2016 in case of an antidumping investigation against Chinese producer/exporters is well applicable in the present investigation vis-à-vis China PR.
31. In view of the same, the Authority has proceeded in this investigation.
32. With regard to the contentions raised by the domestic industry regarding the correctness of EQ Responses, the Authority notes that the issues are addressed at appropriate places in this provisional finding which is self-explanatory.

b) Determination of Normal Value

33. Under Section 9A (1)(c), “normal value” in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non- Market Economy countries

34. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-dumping Rules provides as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without

any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”

35. According to these Rules, the normal value in NME countries (China in the present case) can be determined on any of the following basis:

- a) On the basis of the price in a market economy third country, or
- b) The constructed value in a market economy third country, or
- c) The price from such a third country to other countries, including India.
- d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

i. China PR

36. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR, who have exported the subject goods to India during the POI, have responded in the form and manner prescribed. Thus, none of the producer/exports in the present investigation from China PR could be found to be operating under market economy condition for determination of normal value in terms of Para-6 of Annexure-1 to the Rules. Under this circumstance, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese producers/exporters and the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules supra.

37. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No such information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country at this stage. Therefore, for the purpose of preliminary determination, the Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis.

38. The Authority provisionally determines the Normal Value for China PR on available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration has been determined based on constructed costs of production, duly adjusted to include selling, general & administrative costs and profits. The normal value so determined is US\$ ***/kg.

ii. Japan

39. The Authority notes that none of the producers/exporters from Japan has responded to the Authority in the present investigation. In view of the same, the Authority has determined provisional weighted average normal value at ex-factory level for the PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules which is US\$ ***/kg.

iii. Korea RP

40. The Authority notes that EQ Responses has been filed by two producers from Korea RP namely M/s BASF Company Ltd and M/s Hanwha Fine Chemical Corporation.

BASF Company Ltd

41. The authority notes that BASF Company Ltd (“BASF”) has submitted the exporters’ Questionnaire response claiming to be a producer cum exporter of subject goods and informed that it has exported the subject goods directly to India. The authority notes that BASF has submitted details about domestic sales in Appendix-1.

42. To determine the normal value, the authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80%, then the authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. It was also noted that the loss making transactions were more than 20% of the total domestic sales. Therefore, the Authority has proceeded to determine the normal value based only on the profitable sales in terms of the provisions of Annexure I of the AD Rules.

43. BASF has claimed adjustment on account of rebate, inland freight and packing cost. The authority has provisionally accepted all the adjustments for the purpose of provisional findings. Accordingly, provisional weighted average normal value at ex-factory level for the PUC produced by BASF is determined as **US\$***Kg.**

Hanwha Fine Chemical Corporation

44. The Authority notes that Hanwha Fine Chemical Corporation (“HFCC”) has submitted the Exporters’ Questionnaire response claiming to be a producer of the subject goods in Korea RP and informed that it has exported the subject goods to India indirectly through unrelated exporters/traders. It has also been submitted by HFCC that the company has exported the PUC to India through three exporters/traders and they have filed EQ Responses along with HFCC.
45. The response filed by HFCC has been examined for the purpose of determination of normal value concerning HFCC. It is noted that HFCC produces main raw material namely TDA and also CDC as intermediates. However, HFCC has not provided the cost sheets for these intermediates captively produced by them. HFCC has provided details of TDA and CDC in Appendix 5 which are claimed to be intermediates produced by them, however details of raw materials to produce these intermediates are not given. It is also noted that in Appendix-4, *** MT of subject goods is shown as Transfer In & Out. In view of deficiencies and gap in various appendices in the EQ Response filed by HFCC, the Authority is not in a position to determine fair cost of the subject goods produced by HFCC for the purpose of OCT tests at this stage and accordingly the normal value claims of HFCC which requires detailed verification is not considered for the purpose of this preliminary findings. In view of the above, the Authority has determined provisional weighted average normal value at ex-factory level for the PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules which is **US\$***kg.**

Normal Value for other producers and exporters in Korea RP

46. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has determined provisional weighted average normal value at ex-factory level for PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules and the same is **US\$***kg.**

c) Determination of Export Price

i. China PR

47. The Authority notes that no producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined provisional weighted average net export price for all producers/exporters in China PR concerning the PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules and the same is **US\$***kg.**

ii. Japan

48. The Authority notes that no producer/exporter from Japan has responded to the Authority in the present investigation. In view of the non-cooperation, the Authority has determined provisional weighted average net export price for all producers/exporters in Japan concerning the PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules and the same is **US\$***kg.**

iii. Korea RP

49. The Authority notes that EQ Responses have been filed by two producers from Korea RP namely M/s BASF Company Ltd and M/s Hanwha Fine Chemical Corporation. While it has been submitted by BASF Company Ltd that they have exported the PUC directly to India, however, it has been submitted by Hanwha Fine Chemical Corporation that they have exported the subject goods through unrelated exporters/traders’ P & Y International Co. Ltd, M/s IMS Corporation and M/s Everlite Korea Co., Ltd has filed their EQ Responses and are cooperating with the Authority.
50. Exporters namely M/s P & Y International Co. Ltd, M/s IMS Corporation and M/s Everlite Korea Co., Ltd has filed their EQ Response and claimed that they have exported the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI.

51. EQ Response have also been filed by M/s TJ AL Mulook General Trading LLC, a UAE based Trading Company, claiming that they have exported the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation through Korean exporter namely M/s P & Y International Co. Ltd.
- a) **BASF Company Ltd**
52. The Authority notes from the EQ Response filed by BASF Company Ltd that BASF Company Ltd has exported the subject goods to India during the POI directly. BASF have reported a total export of ***MT in their Appendix-2 and claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed provisionally. Accordingly, the provisional weighted average net export price has been determined for BASF Company Ltd concerning the PUC is US\$***MT.
- b) **M/s Hanwha Fine Chemical Corporation (Producer) and M/s P & Y International Co. Ltd (Exporter)**
53. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s P & Y International Co. Ltd claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation. Appendix-2 filed by P & Y International Co. Ltd shows that they have exported ***MT of subject goods produced by Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI. P & Y International Co. Ltd has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed provisionally. Accordingly, the provisional weighted average net export price has been determined for P & Y International Co. Ltd concerning the PUC produced by Hanwha Fine Chemical Corporation is US\$***kg.
- c) **M/s Hanwha Fine Chemical Corporation (Producer) and M/s IMS Corporation (Exporter)**
54. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s IMS Corporation claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation. Appendix-2 filed by IMS Corporation shows that they have exported *** MT of subject goods produced by Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI. IMS Corporation has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed provisionally. Accordingly, the provisional weighted average net export price has been determined for IMS Corporation concerning the PUC produced by Hanwha Fine Chemical Corporation is US\$***kg.
- d) **M/s Hanwha Fine Chemical Corporation (Producer) and M/s Everlite Korea Co., Ltd (Exporter)**
55. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s Everlite Korea Co., Ltd claiming themselves as an Exporter of subject goods from Korea RP of the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation. Appendix-2 filed by M/s Everlite Korea Co., Ltd shows that they have exported ***MT of subject goods produced by Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI. M/s Everlite Korea Co., Ltd has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed provisionally. Accordingly, the provisional weighted average net export price has been determined for M/s Everlite Korea Co., Ltd concerning the PUC produced by Hanwha Fine Chemical Corporation is US\$***kg.
- e) **M/s Hanwha Fine Chemical Corporation (Producer), M/s P & Y International Co. Ltd (Exporter) and M/s TJ AL Mulook General Trading LLC, UAE (Trader).**
56. The Authority notes that EQ Response has been filed by M/s TJ AL Mulook General Trading LLC. M/s TJ AL Mulook General Trading LLC have claimed that they are a trading company based in UAE and have Exported the subject goods produced by M/s Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI through the exporter from Korea RP namely P & Y International Co. Ltd. Appendix-2 filed by M/s TJ AL Mulook General Trading LLC shows that they have exported ***MT of subject goods produced by Hanwha Fine Chemical Corporation to India during the POI. M/s TJ AL Mulook General Trading LLC has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, insurance and bank charges and same have been allowed provisionally. Accordingly, the provisional weighted average net export price has been determined for M/s TJ AL Mulook General Trading LLC concerning the PUC produced by Hanwha Fine Chemical Corporation and exported through P & Y International Co. Ltd, is US\$***kg.
- f) **Export Price for non-cooperating producers and exporters from Korea RP**
57. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in Korea RP, the Authority has determined the provisional weighted average net export price for the PUC on the basis of best available information as per Rule 6(8) of AD Rules and the same is US\$***per/MT.

d) Determination Of Dumping Margin

58. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from subject countries has been determined by the Authority and the same is as follows;

S.No	Country	Producer	Exporter	Normal Value - US\$/Kg	Export price - US\$/Kg	Dumping Margin - US\$/Kg	Dumping Margin - %	Dumping Margin Range- %
1	China PR	Any	Any	***	***	***	***	15-25
2	Japan	Any	Any	***	***	***	***	5-15
3	Korea RP	Hanwha Fine Chemical Corporation	PP& Y International Co. Ltd	***	***	***	***	10- 20
4	Korea RP	Hanwha Fine Chemical Corporation	Everlite Korea Co., Ltd	***	***	***	***	5-15
5	Korea RP	Hanwha Fine Chemical Corporation	IMS Corporation	***	***	***	***	5-15
6	Korea RP	Hanwha Fine Chemical Corporation	P & Y International Co. Ltd and TJ AL Mulook General Trading LLC, UAE	***	***	***	***	5-20
7	Korea RP	BASF Company Ltd	BASF Company Ltd	***	***	***	***	20-30
8	Korea RP	Any other than the producers at S.No 3 to 7 above.	Any other than the exporters at S.No 3 to 7 above.	***	***	***	***	30-40

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK**i. INJURY EXAMINATION**

59. The submissions concerning injury made by the producers/exporters/importers/other interested parties and considered relevant by the Authority are as follows;
- The pricing of the subject goods in the India market is comparable with other suppliers of the same product such as GNFC, which is the major local player.
 - Imposition of duty may lead to monopoly as GNFC is the sole producer and it will restrict the availability of the material to Indian buyers.
 - Imposition of duties may lead to demand supply gap India. Indian industry cannot supply to the 100% demand. Local manufacturers of downstream products will suffer if anti-dumping duties are imposed. It would all also leave the industries using PUC uncompetitive.

60. The following are the injury related submissions made by the domestic industry in brief;
- i. The injury information provided in the petition shows that although volume parameters such as capacity, production and sales showed a positive trend in a plain reading, a number of other indicators such as capacity utilization, market share, inventory levels etc showed a situation of injury.
 - ii. The Indian market was dominated by dumped imports by holding more than 50% market share in the domestic demand which is very significant and a level enough to render the position of domestic industry seriously vulnerable to such dumped imports.
 - iii. Key parameters relating to the financial situation of the domestic industry, namely profitability, cash profit, ROCE etc turned out to be significantly negative during the POI from a positive situation earlier and, in fact, factors such as return on capital employed, growth etc showed a seriously grave material injury situation.
 - iv. In fact the domestic industry has faced huge financial losses on account of aggressive dumping adopted by producers/exporter from subject countries in the injury period except two base years.
 - v. The domestic industry has been selling the subject goods below its cost of production since the dumped imports were present at a price less than its cost of production seriously injuring the rights of the domestic industry to realize a remunerative price for the subject goods produced by it.
 - vi. The dumped imports were suppressing the domestic prices and serious positive price underselling effects were also evident during the POI. Price undercutting may not be a factor showing injury in this case since the prices are already suppressed and the domestic industry has been selling at a price below its cost. Hence, the question of matching the landed by does not arise and are illogical.
 - vii. The inventory levels of the domestic industry substantially increased which shows clear signs of injury. The increase in production needs to be seen in light of the increase in inventory which signifies the fact that the domestic industry has been prevented from selling more in the market by the dumped imports.
 - viii. An objective and holistic evaluation of various economic parameters clearly demonstrates that dumped imports from subject countries have caused material injury to the domestic industry. The price effect of the dumped imports has been significant on the basis of price suppression and price underselling and as a result of which profitability of the domestic industry has deteriorated and situation of the domestic turned out to be loss making after two initial years in the injury period, thus, the domestic industry has suffered material injury.
 - ix. Even the performance of the domestic industry in terms of volume parameters are also under serious pressure since the capacity utilization have declined and also remained at below par levels while inventory level of the domestic industry have increased and more than 50% of the market share has been held by dumped imports.
 - x. In fact, the marginal growth in production and sale has been negated by the overall losses faced by the domestic industry on account of serious price competition from dumped imports. Domestic industry was forced to sell at a price which has not been remunerative and, in fact, below its cost of production. The domestic industry has, thus, suffered material injury and the injury has been caused on account of dumping from subject countries.
 - xi. It has been submitted by Covestro (Hong Kong) Limited that their pricing is comparable to that of other suppliers including GNFC. The statement has no legal or factual basis and there is no EQ Response filed by Covestro to substantiate their claims.
 - xii. It has been alleged by Covestro that imposition of duty may lead to monopoly as GNFC is the sole producer and it will restrict the availability of the material to Indian buyers. The argument has no legal basis. GNFC is the sole producer of subject goods in India which makes it necessary to protect this company from dumping, else the domestic market will be dominated by foreign players leaving no room for the domestic industry. Also, legally, there is no bar on sole producer to seek protection from dumping. Duties do not ban imports. Imports can be still made but at non dumped prices.
 - xiii. It has been alleged by Covestro that imposition of duties may lead to demand supply gap India. The claim has no basis. AD duties are not against imports per se. It would help to remove the injurious effect of dumping. Demand supply gap, if any, does not disqualify a domestic industry from seeking protection against dumping. This Authority has subjected this issue to examination in plethora of investigations and it was consistently found that demand supply gap, if any, is not a reason to permit dumping.
61. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

62. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Rule 11 of AD Rules read with para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.
- “The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”*
63. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the opposing interested parties and also domestic industry. However, certain specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority are as below;
64. With regard to the contention that the exporters’ price is comparable to that of other suppliers including GNFC in the Indian market, it is noted that the statement do not disprove the claims of dumping and injury raised by the domestic industry and is seen as an unsubstantiated statement.
65. With regard to the contention that the applicant is the sole producer in India and any anti-dumping duties on PUC shall lead to monopoly, it is noted that the submission devoid of any merit legally and factually. Anti-dumping duties, if any, are imposed to correct the trade distorting effects of dumping and the Rules do not preclude a sole producer from seeking protection from dumping.
66. With regard to the contention that the imposition of duties may lead to demand supply gap in India since the domestic industry may not be able to cater to 100% demand in India, the Authority notes that though the domestic industry is not legally bound to meet the entire demand in the country while seeking anti-dumping duties on impacted product produced by it, the fact of the present case is that the capacity set up by the domestic industry is in the same level as that of the demand in the country. It is also noted that the AD duties if imposed are only to remove the injurious effect of dumping and do not envisage any protection beyond the lower of injury or dumping margin and it will not prevent imports per se and the consumers can still import but at an undumped price from subject countries.
67. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India, the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc in accordance with Annexure II (iv) of the Rules supra.

Cumulative Assessment

68. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and*
 - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.*
69. The Authority notes in this respect that:
- The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de Minimis limits prescribed under the Rules.
 - The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

70. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.

ii. VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

a. Demand and market share

71. Authority has defined, for the purpose of the present investigation and this provisional finding, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The Authority has considered imports into India as per DGCI&S on transaction wise to determine the volume and value of imports of PUC into India from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

i) Demand

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Demand	MT	49,531	51,168	57,121	64,398
Indexed	Trend	100.00	103.30	115.32	130.01
Imports from Subject Countries	MT	30,097	32,171	37,232	32,115
Imports from Other Countries	MT	2,438	1,983	1,319	122
Sales of Domestic Industry	MT	16,997	17,014	18,570	32,161
Sales of other Indian Producers	MT	Nil	Nil	Nil	Nil

ii) Market Share of subject countries in Demand

72. Considering imports of subject goods from various sources and sales of subject goods of the Indian Producer, demand was determined and further market share of subject imports, domestic industry and other imports in such demand in India was also examined and the factual position in this respect is as follows;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports from Subject Countries	%	34.32	33.25	32.51	49.94
Imports from Other Country	%	4.92	3.88	2.31	0.19
Sales of Domestic Industry	%	60.76	62.87	65.18	49.87
Sales of other Indian Producers	%	Nil	Nil	Nil	Nil

73. It is seen from the above tables that demand for the product in the country has shown a positive trend and significant growth over the injury period. Any distortions in demand was, thus, not evident. It is also noted that the imports from subject countries held about 50% of the market share during the POI and such share is noted as significant. At the same time, share of imports from other countries declined further and were at negligible levels during the POI.

b. Import volume and market share of subject countries

74. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as per the transaction wise import data provided by DGCI&S. The Authority has relied upon the same for the purpose of this provisional finding. On

the basis of import data on record, the import volume from subject countries is found to be above the de-Minimis levels. Imports volume from subject countries and other countries has been as under: -

	Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Volume	China PR	MT	5,729	6,738	8,572	6,724
	Japan	MT	8,017	9,190	12,322	8,913
	Korea RP	MT	16,351	16,243	16,339	16,479
	Subject Countries Total	MT	30,097	32,171	37,232	32,115
	Other countries	MT	2,438	1,983	1,319	122
	Total imports	MT	32,534	34,154	38,551	32,237
Market Share in Imports	China PR	%	17.61	19.73	22.23	20.86
	Japan	%	24.64	26.91	31.96	27.65
	Korea RP	%	50.26	47.56	42.38	51.12
	Subject Countries	%	92.51	94.19	96.58	99.62
	Other countries	%	7.49	5.81	3.42	0.38

75. It is noted that the imports of the subject goods into India were primarily taking place from subject countries. The share of imports from subject countries increased in absolute terms and it was more than 90% of the total imports into India throughout the injury period including the POI. In fact, imports from subject countries constituted about 99.62% of the total imports into India during the POI. It is also noted that imports from subject countries accounted for very significant proportion of the demand of the product in India. The volume of imports from the subject countries increased in absolute terms and also in proportion to demand in India during the injury period and during the POI. The imports from subject countries which were 30097 MT in the base year increased to 32115 MT during the POI and the same stood at 49.87% in the Indian demand during the POI. The significant share of dumped imports in domestic demand and the growth of the imports from subject countries in absolute terms are very evident.

c. Share of dumped imports in relation to production

76. The Authority notes that the dumped imports from subject countries have increased in relation to the production of the domestic industry also, as is evident from the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports from Subject Countries	MT	30,097	32,171	37,232	32,115
Production of domestic industry	MT	17,875	16,317	23,737	45,680
Imports from subject countries in relation to production of domestic industry.	%	168.38%	197.17%	156.85%	70.31%

77. It is observed that imports from subject countries have been much higher than total Indian production in the base year which stood at 70.31% in the POI. Though the production of the domestic industry was not very high in the initial two years, significant capacity additions were carried out during 2014-15 and during the POI. Even with the increased production figures during POI, imports from subject countries in relation to production in India throughout the injury period and also in the POI remained at a very significant level and such significant levels are also visible vis-à-vis demand of the product in the country. Thus, imports from subject countries have increased in absolute terms and remained at significant levels vis-à-vis production and consumption in India.

iii. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

78. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

79. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports of the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries at the appropriate sections below.

a) Price Undercutting

80. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Particulars	Unit	China PR	Japan	Korea RP	Subject Countries
Landed Value	Rs./KG	123.92	111.57	110.05	113.37
Net Sales realization	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	Negative	Negative	Negative	Negative

81. The authority notes that the price undercutting has been negative from subject countries. Authority also notes that landed value of imports has both depressing and suppressing effect on price where the domestic industry has been constantly forced to reduce its prices to match with the landed value of imports. If the Domestic Industry does not respond to imports by bringing down its prices, it may lose customers and the injury may be severe. In the facts of the present case the domestic industry has been selling the PUC at a rate less than its cost of production incurring losses.

b) Price Underselling

82. The Authority has also examined the price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry for the POI based on Annexure III has been compared with the landed price of imports. Comparison of weighted average NIP of the domestic industry with weighted average landed price of imports shows as follows:

Particulars	Unit	China PR	Japan	Korea RP
Non-Injurious Price	Rs/KG	***	***	***
Landed price	Rs/KG	123.92	111.57	110.05
Price underselling	Rs/KG	***	***	***
Underselling	%	***	***	***
Underselling	% Range	05-20	20-30	20-30

83. It is seen that the landed price of the subject goods from the subject countries were significantly lower than the NIP determined for the domestic industry showing price underselling effects.

c) Price suppression/depression

84. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown in the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of production	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	111.04	136.86	122.79
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	81	60
Landed Value (Subject Countries)	Rs./KG	166.73	162.17	153.64	113.37
Trend	Indexed	100	97.26	92.15	68.00

85. It can be seen from the above table that while the cost of production increased from 100 indexed point in the base year to 122.79 points in the POI, whereas the selling price moved from 100 indexed points in the base year to 60.00 indexed points which shows significant price depression and suppression effect on prices on account of the dumped prices as the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to increase in costs. It is evident that the landed price of imports was causing price depression/suppression and causing serious price effects on the sales realization of the domestic industry apart from price underselling.

Economic parameters of the domestic industry

86. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

d. Capacity & Capacity Utilization

87. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity MT	MT	14,000	14,000	64,000	64,000
Production	MT	17,845	16,317	23,737	45,680
Capacity utilization	%	127.68	116.55	37.09	71.38

88. It is observed that the domestic industry undertook capacity additions during 2014-15 and the capacity thereafter remained the same during the POI as well. Though the dip in capacity utilization can be attributed to increase in capacity, what is noteworthy in the above data is the fact that the capacity utilisation remained at 71.38%.
89. Domestic industry claimed that dumped imports prevented them from operating at an optimal level of capacity utilisation and such below par utilisation of capacity was when there was robust growth in demand in the country for the subject goods. Capacities were increased by the domestic industry to cater to the significant domestic demand, however, such increases did not help the domestic industry to achieve overall good performance in terms of both volume and value since there have been significant presence of dumped imports from subject countries. It has been submitted by the domestic industry that had the dumped imports been not holding almost 50% of the market share, the domestic industry would have achieved a much better level of capacity utilisation which shows domestic industry suffered material injury on capacity utilisation.

e. Production

90. Production of the domestic industry is given in the table below:-

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	MT	17,875	16,317	23,737	45,680
Demand	MT	49,531	51,168	57,121	64,398
Production in relation to Demand	%	36.09	31.89	41.56	70.93

91. It is noted that production of the domestic increased by the POI. Domestic industry claimed that increase in production should not be seen as a standalone parameter since the capacity utilisation remained much lower than the desirable levels at 71.38% during the POI. The domestic industry could have catered to the entire Indian demand on its own during the POI had there been no dumping.
92. It has also been submitted by the domestic industry that though the capacity and production increased over the base year, the associated price parameters showed sharp declines and financial losses have been suffered by the domestic industry effectively negating the benefits which ought to have been achieved by the domestic industry by virtue of increases in volume parameters such as capacity and production.

f. Sales volume and market share

93. Sales volume of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Domestic sales	MT	16,997	17,014	18,570	32,161
Demand	MT	49,531	51,168	57,121	64,398
Market Share of domestic industry in Demand	%	34.32	33.25	32.51	49.94

94. It is observed that sales of the domestic industry showed increasing trend. The trend in sales during POI has been similar to the development in capacity and production during the POI. Domestic industry claimed that even though sales volumes increased by POI, the capacity utilisation has been below the desired levels and almost 50% of the market share during the POI has been held by dumped imports which shows the domestic industry had the potential to cater much more to the domestic demand but was prevented from doing so due to the dumped imports. Thus, the situation of sales during the POI in terms of volume also showed signs of injury and stagnant growth. Also, during

the same period the associated price parameters showed sharp declines and even financial losses have been suffered by the domestic industry.

95. Also, even though the sales volumes were increased, it was at the best achieved by adjusting the price to match the landed price of imports. In essence, increase in sales volume did not create any bottom line improvement since there was significant volume of dumped imports from the subject countries in the Indian market. It is having also been submitted by the domestic industry with regard to the position of sales that the prudence of increase in volume parameters as such were not reflected in the overall performance of the domestic industry which is reflected in the financial parameters. Increases in volume parameters may at the best have neutralised some effect of fixed costs on performance but the same was not adequate to bring an overall improvement in the performance due to dumped imports from subject countries in the Indian market during the POI.
96. The Authority notes in this respect that the sales volume of the domestic industry among other volume parameters improved over the injury period and the POI. However, as noted herein above, the market share of imports from subject countries have been at significant levels during the POI and it cannot be denied that the dumped imports have not been causing any adverse effects on the actual and potential sales volumes of the domestic industry during the POI. It is also noted that though the sales volume increased in absolute terms, the domestic industry was having significant unutilised capacity and have been left to reduce the prices further to maintain the sales volume and ease the pressure of increasing stock.

g. Inventories

97. The position of inventories noted as average stock with the domestic industry moved as follows;

	Units	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Stock	MT	748	776	1,625	2,107

98. It is noted that inventories with the domestic industry has been showing increasing trend and has been at the highest level during the POI. It is further noted that the increase in inventories when the demand and production has been showing increases in the similar period depicts adverse volume effects on the domestic industry. Thus, the adverse effects of dumping on inventory position are visible.

h. Profit/Loss

99. The profitability of the domestic industry is given in the following table;

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Profits	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	48.37	(89.46)	(131.64)
Profits	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	48.42	(97.74)	(249.08)

100. It is noted that there have been distortions on the profitability of the domestic industry over the injury period and the domestic industry started incurring significant losses in the POI and the immediate previous year. The domestic industry was earlier earning profits. It is noted herein above that the landed price of imports were creating price depression/suppression and underselling effects on the domestic prices in the same period. The impact of such landed prices is evident in financial loss situation of the domestic industry.

i. Return on capital employed

101. Information regarding return on capital employed is given in the table below;

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	51	(6)	(21)

102. The Authority notes that return on capital employed of the domestic industry has deteriorated significantly over the injury period and become seriously negative during the POI and through the two previous years. The trend is comparable to that of profitability. It has been submitted by the domestic industry that significant and severe price pressure from dumped imports is the reason for such significant downfalls in profitability and ROCE that imposition anti-dumping at the earliest are essential to ensure the survival of the domestic industry. It has also been submitted that the growing financial losses can only be arrested by curbs on dumped imports by way of interim measures pending further investigation.

j. Cash Flow

103. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table;

	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	59	(53)	(149)

104. It is seen that the cash profits of the domestic industry declined over the injury period and has been negative in the POI in comparison to base year.

k. Factors affecting domestic prices

105. Change in cost structure, competition in the domestic market and prices of competing substitutes, if any, have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic industry. It is noted that the petitioner in the present investigation is the sole producer of the subject goods in India which rules out adverse effects of any unhealthy inter se competition. There has not been any significant change in the cost structure during the POI. However, landed price of subject imports has been below the cost of production and fair selling price of the domestic industry. It could not be concluded that inter-se competition or any such change in cost structure led to decline in the prices of the domestic industry.

l. Productivity

106. Authority notes that productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity per day shows an increasing trend, and it cannot be construed that productivity per day has been a cause any of injury to the domestic industry.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	87.40	28.94	55.69
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	91.28	132.80	255.56

107. It is also noted that the productivity per employee may not be a relevant factor in the facts of this case since there has been additions in capacity and level of employees in the POI. However, productivity per day shows the indicative trend vis-à-vis productivity and has been examined as above.

m. Employment and Wages

108. The employment level has shown similar trend as that of capacity and production. Wages per kg which has shown an increase. It has been submitted by the domestic industry that the wage increases are in line with the statutory requirements and there haven't been any extra ordinary increases in wages paid by the company. Thus, it cannot be said that wages and employment as such had some adverse impact on the domestic industry. It has been submitted by the domestic industry that they have the potential to create more employment provided a fair trade situation by way of imposition of anti-dumping duty on dumped imports of subject goods from subject countries is.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	104.44	458.89	458.89
Wages	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	208	185

n. Growth

109. The Authority notes that growth of the domestic industry is negative in a number of parameters. Negative growth of domestic industry in many parameters has been visible when the market demand for the product showed consistent growth which inter alia shows that the domestic industry was prohibited from taking benefits of such positive market situation due to significant presence of dumped imports with significant adverse price effects.

o. Ability to raise capital investment

110. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made additions in capacity. However, despite these investments and additions in capacity, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected if the dumping of the subject goods is not addressed.

p. Level of dumping & dumping margin

111. It is noted that the imports from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices and the margins of dumping are significant.

G. CONCLUSIONS ON INJURY

112. On an examination of various injury parameters, it is noted that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the PUC in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
113. Imports of the product were creating underselling and price depression/suppression effects. Further, whereas cost of production has been increasing over the injury period, the selling price of the domestic industry shown a declining trend and the domestic industry could not even recover the cost of production that the domestic industry suffered financial losses in the POI. The dumped imports were ,thus, depressing/suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increase.
114. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is noted that the demand for the product and other volume parameters concerning the domestic industry have improved during the POI, however, domestic industry could not improve its profitability proportionately as dumped imports continued to hold significant share in the market. Resultantly, the domestic industry started incurring huge financial losses. Even

though the domestic industry could increase its sales volumes, the same did not create any positive effect on the profitability since such increased sales volumes were achieved by matching the dumped price of subject goods from subject countries.

115. Profitability of the domestic industry declined continuously and the domestic industry has been making financial losses during the POI. Both return on capital employed and cash profits were negative during the POI. Also, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, return on capital employed etc remained negative and shows an adverse impact on the domestic industry due to the dumped imports.
116. Thus, after taking all such factors into consideration, the Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury.

H. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

117. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping from subject countries and material injury to the domestic industry has been done as follows:

(a) Volume and prices of imports from third countries

118. The imports from the countries other than the subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Imports from other countries accounted for less than 0.5% in total. Thus, it cannot be said that imports from other countries are causing injury.

(b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

119. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject countries compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like article and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

120. The Authority notes that demand for the product showed increase during the injury period and also during the POI. Thus, it can be concluded that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

121. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(e) Export performance of Domestic Industry:

122. The details of exports by the domestic industry is as follows;

Period	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Exports	MT	120	-	2,714	14,947
Trend	Indexed	-	-	100	429

2. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, the exports by the domestic industry have increased during the POI. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of any injury.

(f) Productivity of the Domestic Industry

123. The Authority notes that the deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

(g) Performance of the domestic industry with respect to other products

124. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

I. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

125. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially injured over the injury period and during the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

- Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject countries have increased in absolute terms. Also, the landed price of imports has been declining significantly over the injury period and through the POI.
 - Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.
 - Market share of dumped imports in India remained at about 50% during the POI which is a significant percentage and that too when the demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the robust demand in India.
 - The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand. The domestic industry had significant unutilised capacity in the POI even though the demand had increased.
 - Inventories of the domestic industry have been on the rise, as the domestic industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
 - There is significant price suppression and depression due to low priced dumped imports coming in to India.
 - The domestic industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. This is evident from the fact that the domestic industry was earning decent profits and return on capital employed till 2013-14. However, especially during the POI, the profits and returns have turned into huge losses and negative situations.
126. The above analysis indicates that the domestic industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India from subject countries. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from subject countries and the material injury suffered by the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

127. The Authority has determined Non Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the anti-dumping Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries as follows;

S.No	Country	Producer	Exporter	Non Injurious Price – US\$/Kg	Landed price - US\$/Kg	Injury Margin - US\$/Kg	Injury Margin - %	Injury Margin Range - %
1	China PR	Any	Any	***	***	***	***	10-20
2	Japan	Any	Any	***	***	***	***	20-30

3	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Fine	P & Y International Co. Ltd	***	***	***	***	30-40
4	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Fine	Everlite Korea Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
5	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Fine	IMS Corporation	***	***	***	***	20-30
6	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Fine	P & Y International Co. Ltd and TJ AL Mulook General Trading LLC, UAE	***	***	***	***	30-40
7	Korea RP	Hanwha Chemical Corporation	Fine	a) P & Y International Co. Ltd b) Everlite Korea Co., Ltd c) IMS Corporation d) TJ AL Mulook General Trading LLC	***	***	***	***	30-40
8	Korea RP	BASF Company Ltd	Company	BASF Company Ltd	***	***	***	***	30-40
9	Korea RP	Any other than the producers at S.No 3 to 8 above.		Any other than the exporters at S.No 3 to 8 above.	***	***	***	***	35-45

K. CONCLUSIONS ON INJURY AND CAUSATION

128. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this preliminary finding, the Authority concludes that:

- I. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its normal value, resulting in dumping.

- II. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.
- III. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

L. Indian Industry's Interest & Other Issues:

129. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from Iran in any manner and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain multiple sources of supply.

M. Recommendation

130. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from subject countries below their normal values.
 - The domestic industry has suffered material injury.
 - Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from subject countries.
131. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is required to offset dumping and consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from subject countries in the form and manner described hereunder.
132. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, provisional antidumping duty as per amount specified in the table below is recommended to be imposed from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from subject countries.

DUTY TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	29291020	Toluene di-isocyanate	China PR	China PR	Any	Any	0.26	Kg	US\$
2	29291020	Toluene di-isocyanate	China PR	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	Any	Any		Kg	US\$

							0.26		
3	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	China PR	Any	Any	0.26	Kg	US\$
4	29291020	Toluene di-isocyanate	Japan	Japan	Any	Any	0.14	Kg	US\$
5	29291020	Toluene di-isocyanate	Japan	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	Any	Any	0.14	Kg	US\$
6	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	Japan	Any	Any	0.14	Kg	US\$
7	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Korea RP.	Hanwha Fine Chemical Corporation	a)P & Y International Co. Ltd b) Everlite Korea Co., Ltd c)IMS Corporation d)TJ AL Mulook General Trading LLC	0.17	Kg	US\$
8	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP	Korea RP	BASF Company Ltd	BASF Company Ltd	0.31	Kg	US\$
9	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP	Korea RP	Any combination other than			Kg	US\$

					mentioned in Sl. No.7 &8 above		0.40		
10	29291020	Toluene di-isocyanate	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	Korea RP.	Any	Any	0.40	Kg	US\$
11	29291020	Toluene di-isocyanate	Korea RP.	Any country other than those subject to Anti dumping Duty	Any	Any	0.40	Kg	US\$

N. FURTHER PROCEDURE

133. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings: -

- a) The Authority invites comments on these provisional findings from all the interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- b) Exporters, importers, the applicant and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within forty days from the date of the publication of these preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings.
- c) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- d) The Authority may hold oral hearing to hear the interested parties orally before notifying the final findings.
- e) The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-dumping Rules before announcing the final findings.

INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority